



क्या इतना आसान है
पार्लियामेंट की
सिक्कोरिटी
को भेदना

(राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका)

युवक

स्थापित : सन् 1950



नये चेहरों पर भरोसा जता कर
भाजपा ने राजनीती में
कर दिया बड़ा उलटफेर



*Make your life more
Comfortable*

BEBER
BATH FITTINGS



Make way for iconic luxury....



Mathura
Mobile +91-9412280225

युवक

वर्ष - 08, अंक - 9, दिसंबर 2023

संस्थापक सम्पादक
स्व. श्री प्रेमदत्त पालीवाल

संरक्षक
स्वामी महेशानंद सरस्वती
आनंद कुटीर, मोतीझील, श्रीधाम वृंदावन

सम्पादक
डॉ. वंदना पालीवाल*

प्रबंध संपादक
देवेन्द्र दत्त पालीवाल

कॉन्सेप्ट एडिटर
अजय शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
इंजी. ज्ञानेंद्र गौतम

साहित्य संस्कृति संपादक
आदर्श नंदन गुप्त

सलाहकार संपादक
डॉ. महेश चंद्र धाकड़

वाइस प्रेसीडेंट
(सर्कुलेशन/एडवर्टाइजिंग)
बृजेश शर्मा

सीनियर ग्राफिक डिजायनर
रानू शर्मा

लीगल एडवाइजर
एड. विकास गौतम

विजुअलाइजर
मनोज कुमार/सौरभ सिंह

युवक

ब्यूरो ऑफिस

दिल्ली विनय शर्मा, फोन: 09555220374

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती सुधारानी पालीवाल द्वारा युवक प्रेस गैस
बंगला नं. 4, जीवनी मंडी, आगरा 282004 (उ.प्र.)

से मुद्रित व प्रकाशित

सम्पादक- डॉ. वंदना पालीवाल * पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी,

R.N.I. No.- 2166

सब्सक्रिप्शन भारत में न्यूनतम एक वर्ष के लिए (12 अंक) शुल्क

340+60 (पोस्टल चार्ज)= रुपये 400

कृपया डीडी (आगरा में)

YUVAK MASIK PATRIKA के नाम देय हो।

GSTIN NO. 09AGNPP9720D122

DAVP CODE-132863

उपरोक्त अंक में प्रकाशित रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पत्रिका में छपे किसी भी लेख के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न रचनाओं के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री/विज्ञापन आदि से संपादक/प्रकाशक/मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही एवं पूछताछ की अवधि से तीन माह के अंदर की जा सकती है। इसके बाद किसी भी प्रकार की कार्यवाही, पूछताछ के लिए हम बाध्य नहीं हैं। प्रेषित स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की रिश्तित में न्याय क्षेत्र सिर्फ आगरा होगा।

संपादकीय कार्यालय

युवक (हिन्दी मासिक)

बंगला नं. 4, जीवनी मंडी, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश
पत्रिका से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
सम्पर्क सूत्र +91 9415407766

लेख अथवा रचनाएं हमें ईमेल करें
yuvakmagazine@gmail.com

Website - www.progressiveyuvak.com



जरूर पढ़ें

संसद हमला

18 | संसद में छोड़े गये 'पीले रंग' में छिपे...

शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भारतीय संसद के अंदर शायद कुछ बहुत बड़ा होना मुक़रर था क्योंकि 22 बरस पहले आतंकवादियों द्वारा दिया एक नासूर जख्म जो प्रत्येक 13 दिसंबर की तारीख के दिन याद करके हरा हो जाता है। खैर, गनीमत ये समझें कि संभावित घटना 'पीले रंग' तक ही सीमित रही, वरना कुछ 'काला' भी हो सकता था। 13 तारीख वैसे भी संसदीय परंपरा के लिए 'काली तारीख' ही है। केन्द्र सरकार इस अशुभी घटना को हल्के में कतई न ले।

विशेष

शख्सियत

46 | सैम बहादुर के बहाने, याद जनरल मानेकशा की

सैम हॉरमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशा को देश 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारतीय थल सेना का कुशल नेतृत्व करने वाले एक सेनाध्यक्ष के रूप में कृतज्ञ भाव से याद करता है। वे फील्ड मार्शल का पद हासिल करने...



जरूर पढ़ें

सख्ती

14 | अब कौन पहुंचायेगा सरकारी संपत्ति...



जिस बात का देश से प्रेम करने वाले हरेक नागरिक को विगत दशकों से इंतजार था, वह अब हो गई है। अब किसी आंदोलन के दौरान कथित आंदोलनकारी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगे। यदि नुकसान पहुंचाया तो उन्हें सख्त सजा होगी। हमारे यहां सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने वाले आमतौर पर सरकारी बसों, इमारतों, रेलों और दूसरी सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेशर्मा से तोड़ते रहे हैं।

विशेष

राजनीति

34 | शिखर से शून्य की ओर जाता दिख रहा है...

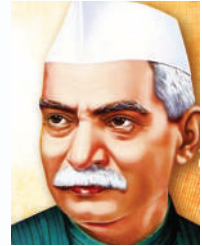
मायावती के फैसले ने यूपी की सियासी गर्मी को बड़ा दिया है। क्योंकि उन्होंने बसपा के किसी नंबर दो के दमदार नेता की बजाय भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ज्यादा उचित समझा। यही परंपरा मान्यवर कांशीराम निभाते तो आज मायावती बसपा सुप्रीमो नहीं हो पातीं।

विधानसभा

विशेष

06 | बेहद दिलचस्प रहा डॉ. राजेंद्र प्रसाद के...

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। बता दें कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़-चढ़कर हिस्सा लिया था। वह कांग्रेस में शामिल होने वाले बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे।



44

कहानी

50

कविता



जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण के संबोधन में जलवायु परिवर्तन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन भी एक है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत इन चिंताओं को कम नहीं आंकता है। इसको लेकर भारत सचेत है। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी दुबई में इस मसले पर हो रहे मंथन के दौरान आई है। खास बात यह है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी28 में इस मामले में भारत के प्रयासों की तारीफ की गई है। सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस साल पिछली बार की तुलना में एक पावदान ऊपर (सातवें स्थान) पहुंच गया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शुमार है। यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक तैयार करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी की गई। यह देश दुनियाभर में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। सूचकांक में भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। यह अलग बात है कि रिपोर्ट में जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंकिंग मिली है। महत्वपूर्ण यह है कि सूचकांक में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। सूचकांक पर आधारित यह रिपोर्ट कहती है, 'हमारा डेटा दिखाता है कि प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस श्रेणी में, देश दो डिग्री सेल्सियस से नीचे के मानक को पूरा करने की राह पर है। हालांकि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में थोड़ा सकारात्मक रुझान दिखाता है, लेकिन यह रुझान बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।' जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ अपने राष्ट्रीयस्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और

नवीकरणीय ऊर्जा घटकों के घरेलू विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके बावजूद, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें अभी भी तेल और गैस के साथ-साथ कोयले पर भारी निर्भरता से पूरी हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे जर्मनी के नेता और यूरोपीय संसद के सदस्य पीटर



जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता खास है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समझौते पर चर्चा की थी। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ खत्म हुए 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।

लीसे ने भारत के संदर्भ में अहम टिप्पणी कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बेहद कम है। इसलिए भारत को चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने भारत के पक्ष में एक बात यह भी कही कि जब जर्मनी में लोगों के पास दो कार हैं, तो भारतीयों के पास भी एक कार तो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम होने के बावजूद इस सम्मेलन में भारत को अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जकों के साथ जोड़ने के ठोस प्रयास किए गए हैं। यूरोप में तमाम लोग चीन और भारत को और कभी-कभी खाड़ी देशों को एक ही नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

यह नजरिया पूरी तरह अस्वीकार्य है। इन देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी वैश्विक वैज्ञानिकों की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पिछले साल लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर दो टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच गया, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। इस रिपोर्ट में चेताया गया है कि अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चार्ट में शीर्ष पर है। अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति 14.9 टन सीओ 2 उत्सर्जित करता है। इसके बाद रूस (11.4), जापान (8.5), चीन (8), और यूरोपीय संघ (6.2) हैं।

दरअसल औसत तापमान, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम के विभिन्न आयामों में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बढ़ती बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र के जलस्तर में बढ़ती हो जाती है। इसका असर इंसान, जानवरों और वनस्पतियों पर पड़ता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। इससे निपटना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आंकड़े भयावह हैं। 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फॉरेनहाइट (अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस) बढ़ा है। इसके अलावा पिछली सदी से अब तक समुद्र के जलस्तर में भी लगभग आठ इंच की बढ़ती हुई है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता खास है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समझौते पर चर्चा की थी। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ खत्म हुए 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। ■

डॉ. वंदना पालीवाल

संस्कृति का सम्मान पर्यटन का संवर्द्धन



यूपी में सर्वाधिक
31 करोड़ से अधिक
घरेलू पर्यटकों का
आगमन (वर्ष 2022)

नं.
उत्तर
प्रदेश
देश में

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना के अंतर्गत 389 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक पर्यटन स्थल का विकास

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 लागू, **रु. 1.29 लाख करोड़** का निवेश, **3.52 लाख** रोजगार का सृजन

विकसित होंगे **रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, सूफी सर्किट, क्राफ्ट सर्किट स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, जैन सर्किट** तथा **वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट**

होटल इंडस्ट्री के लिए **निवेश आधारित सब्सिडी** की व्यवस्था, होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा, पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यावसायिक की जगह होंगी औद्योगिक

अयोध्या धाम में **सुश्रीव किला पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ** का निर्माण अयोध्या में बनेगा **5 एकड़** में मंदिर संग्रहालय

अयोध्या में दीपोत्सव, ब्रज में रंगोत्सव एवं **काशी में देव दीपावली** का भव्य आयोजन काशी में **मां अन्नपूर्णा** की प्रतिमा **100 वर्ष बाद पुनः प्रतिष्ठापित**

मथुरा के **बरसाना** व प्रयागराज में **झूंसी से त्रिवेणी पुष्य** तक एवं **विध्याचल में रोप-वे** का निर्माण

प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए **2500 करोड़ रुपये** का प्रावधान प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में **निषादराज गुह्य पर्यटन स्थल** व बहराइच में **महाराजा सुहेलदेव स्मारक** का निर्माण

उत्तर प्रदेश **ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद** एवं **मैनिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद** का गठन

वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती एवं **संक्रिसा में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव** का आयोजन, **वाराणसी व मगहर में कबीर फेस्टिवल**

दुनिया के सबसे लंबे चिंटर कूज, वाराणसी से डिब्रूगढ़-असम तक (3,200 किमी.) **'गंगा विलास'** की शुरुआत

दुधवा टाइगर रिजर्व, पौलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्नियाघाट वन्यजीव पार्क बने प्रमुख लोकप्रिय ईको-पर्यटन स्थल

बरेली में **रु. 232.21 करोड़** की लागत से **नाथ नगरी कॉरिडोर** का होगा निर्माण नाथ मंदिरों के साथ बनेगा वैदिक पुस्तकालय, भण्डारा एवं रुद्रामिषेक कर्मकाण्ड हॉल

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए **वन डिस्ट्रिक्ट-वन डेस्टिनेशन (ओडीओडी)** योजना शुरू

यूपी वॉटर टूरिज्म एंड एडवेंचर, स्पोर्ट्स पॉलिसी-2023 को मंजूरी जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, नदियों, विभिन्न जल निकायों, भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों एवं जल क्रीड़ा को प्रोत्साहन

बेहद दिलचस्प रहा डॉ. राजेंद्र प्रसाद के

राष्ट्रपति बनने का फिरसा, देश के हित में किए कई काम

डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने देश के हित में कई अहम कदम उठाए थे। वह महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे।





अनन्या मिश्रा

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। बता दें कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। वह कांग्रेस में शामिल होने वाले बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। इसके साथ ही राष्ट्र के प्रति सम्मान के लिए राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने देश के हित में कई अहम कदम उठाए थे। आइए जानते हैं डॉ राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

जन्म और शिक्षा

बिहार के सिवान जिले के जिरादेई गांव में एक कायस्थ परिवार में 3 दिसंबर 1884 को डॉ राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। उनका विवाह महज 12 साल की उम्र में हो गया था। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। वह बचपन से पढ़ाई में काफी तेज थे। राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जिसके कारण उनको हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद साल 1902 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में लिया था। आप उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कॉपी चेक करने वाले टीचर ने राजेंद्र प्रसाद की शीट पर 'परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज्यादा बेहतर है' लिखा था।

सामाजिक कार्य

डॉ राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य किए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने साल 1906 में बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यह एक अलग और नए किस्म का गुप था। इस गुप ने बिहार से कई बड़े नेता दिए। जिनमें से डॉ. अनुग्रह नारायण और श्री कृष्ण सिन्हा मुख्य रहे।

महात्मा गांधी का साथ

डॉ राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने चंपारण आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को काम करते देखा, तो वह खुद को रोक न सके। जिसके बाद वह भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी के नजरिए का पूरा समर्थन करते हुए छुआछूत और जातिप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने

लगे। उनके जीवन पर महात्मा गांधी ने इतना गहरा असर किया था कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने घर में काम करने वालों की संख्या घटा दी थी। वह अपने घर के सारे काम खुद करते थे। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था।

सरल दिल के व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद

डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से बेहद विनम्र और सरल व्यक्ति थे। साल 1914 में बंगाल और बिहार में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने लोगों की खूब सेवा की। वहीं साल 1934 में जब बिहार मलेरिया से जूझ रहा था, उस वक्त भी उन्होंने खुद पीड़ितों को दवाईयां और कपड़े बांटने का काम किया था।

ऐसे जुड़ा कांग्रेस से रिश्ता

साल 1934 से लेकर 1935 तक वह भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। वहीं साल 1935 में डॉ. प्रसाद को कांग्रेस के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद साल 1939 में उन्हें जबलपुर सेशन का भी अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधीजी के बीच की दूरियों को मिटाने की भरकस कोशिश की थी।

देश के लिए योगदान

देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को वह देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। हालांकि पंडित जवाहर लाल नेहरू उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने से सहमत नहीं थे। लेकिन महावीर त्यागी और सरदार पटेल के प्रयासों से उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। जिस दिन देश का संविधान भी लागू होने जा रहा था। उससे एक दिन पहले यानी की 25 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद की बहन का निधन हो गया था। लेकिन उन्होंने देश को परिवार से ऊपर रखते हुए पहले गणराज्य की स्थापना की और फिर दाह संस्कार में हिस्सा लिया। 1962 तक राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने देश की सेवा की और फिर वे पद त्याग कर पटना जनसेवा के लिए चले गए।

मौत

भारत की आजादी और आजादी के बाद भी देश के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद का किया गया योगदान सराहनीय है। भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई देशों का दौरा किया था। वहीं 28 फरवरी 1963 में डॉ राजेंद्र प्रसाद का पटना में निधन हो गया। ■



वनदेवी वृन्दा और वृन्दावन

वन सेवी साधकों की दृष्टि से खास वृन्दा-वन

आज वृन्दावन क्या है? वृन्दावनवास का भाव क्या है? अब महानगरीय शैली में ढले वृन्दावन से वृन्दादेवी के उस पवित्र वन का अनुभव कैसे हो, जिसे वन उपासक साधकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीया? उस वृन्दावन की अनुभूति अब कैसे हो, जिसके विषय में श्रीमद्भागवतकार व्यासजी कहते हैं- ह्यवनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नव काननम्।...

डॉ. राजेश शर्मा

यह गाय और अन्य पशुओं के लिए घास, पौधों और लताओं की सुलभता के साथ हरा-भरा है... कहीं गया वह वृन्दावन जिसकी तुलना महाकवि कालिदास स्वरचित महाकाव्य रघुवंश में चैत्ररथ के उद्यान से करते दिखते हैं? जिस वृन्दावन को देख 1729-30 ई० के दौरान भारत यात्रा को आया फ्रांसीसी यात्री जैक मांट कह उठा... 'धूल भरे मैदानों में वृक्षों की अधिकता के चलते यह एक हरे द्वीप की तरह है...' आज वृन्दावन में वैसा कुछ नहीं दिखता, जो पुराणों से दर्शित है। इसी क्रम में वन-देवी वृन्दा की जो सांस्कृतिक यात्रा, वन-सेवी उपासक साधकों की वाणी से उद्घाटित है, का परिदर्शन भी आज सहजता से नहीं होता। पिछले लगभग 500 वर्षों के दौरान इन साधकों ने वृन्दादेवी को जिस भाव के साथ जिया, वह इस वन-देवी का ऐसा दिव्य स्वरूप है, जिसकी चर्चा प्रायः कम ही हुई है। विक्रम की 16वीं सदी के साथ ही वृन्दा-विपिन और यहाँ की वनदेवी वृन्दा का स्वरूप विविधताओं के साथ दिखता है। ब्रजस्थ विभिन्न वैष्णव परम्पराओं में वृन्दा का जो स्वरूप दर्शित है, वह वनदेवी वृन्दा को समझने की सहज दृष्टि है।

वृन्दा से जुड़े पुराण आधारित सन्दर्भ या तुलसी का वन ही वृन्दा के इस विपिन की पूर्ण परिभाषा नहीं, अपितु इस पवित्र वन में साधनारत साधकजनों ने वन देवी वृन्दा को जिस भाव से जिया, वह अद्भुत है। यह अद्भुतता हमें दिव्य वृन्दा-विपिन की अलौकिक छटा के मध्य ला खड़ा करती है। यह धरातल साधकों का है, उन महासाधकों का जिनके लिये श्रीकृष्ण कथा द्वारकालीन नहीं, वर्तमान है। साधकों के इष्ट युगल-स्वरूप श्रीराधाकृष्ण और उनके सखी परिकर की नित्य विहार स्थली है, यह दिव्य वृन्दावन। वन देवी वृन्दा की कृपा प्राप्त कर साधकजन प्रभु की सुखद लीलाओं में सहभागिता की कामना करते हुए इस पवित्र स्थली में मृत्यु पर्यन्त बने रहने की अभिलाषा रखते हैं। भले ही शास्त्रसम्मत सप्तपुरियाँ मोक्ष प्रदायक हों पर वृन्दा-विपिन के साधक जानते हैं ये वह दिव्य स्थली है, जहाँ भक्ति का भी उद्धार हुआ- 'धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च...' निकुंजविहारी श्रीकृष्ण इस पवित्र स्थल को क्षण भर के लिये भी नहीं त्यागते। वृन्दावन में भजन करते हुए साधक की धाम प्राप्ति (निकुंजवास) होने पर, उसके भाग्य की सराहना करते हुए, गायन होता है- भाग बड़े बिन्दावन पायौ।

यहाँ वृन्दा-विपिन को जीने का भाव अद्भुत है। साधनजन जीवनपर्यन्त इस पवित्र भूमि को न त्यागने हेतु दृढ़ संकल्पित रहते हैं। मृत्यु उपरान्त भी वृन्दावनवास को प्राप्त कर इस भूमि पर निवास का भाव यहाँ इस वन के प्रति ममत्व और श्रद्धा से जुड़ा उच्चतम उदाहरण है। वृन्दावन की गलियों में भ्रमण करते हुए दर्शित होने वाली समाधियों की समृद्ध



वृन्दावन के गोविन्ददेव मन्दिर में स्थित वृन्दादेवी की ख्याति विभिन्न संदर्भों से उद्घाटित है। यहाँ वृन्दादेवी का भव्य मन्दिर हुआ करता था। औरंगजेब के शासनकाल में जब यहाँ के प्रायः श्रीविग्रह ब्रज से बाहर गये, उस दौरान वृन्दावन के प्रसिद्ध गोविन्ददेव मन्दिर में विराजित वृन्दा देवी का श्रीविग्रह भी यहाँ से ले जाया गया।

श्रृंखला, इस बात की साक्षी है। वृन्दा-विपिन उपासी साधकों का भाव है कि भौतिक वृन्दावन में अर्जित भजन तथा जीवनभर की धाम निष्ठा के सहारे वे उस दिव्य वृन्दा-विपिन की लता-निकुंजों में प्रवेश के अधिकारी होते हैं, जहाँ श्यामा-श्याम की नित्य लीलाएँ हैं और उन भक्त साधकों का वह परिकर भी विद्यमान है, जिन्होंने इस दिव्य वृन्दावन की प्राप्ति की। 16वीं सदी में युगल सरकार राधाकृष्ण की भक्ति के उद्देश्य से पधारे साधकजनों ने यहाँ साधनारत रहकर इस दिव्यता का अनुभव किया। यहाँ वृन्दावन मात्र तुलसी का पवित्र वन नहीं, यहाँ की हर लता-दुम वृन्दा का ही स्वरूप है। साधकों ने इस भाव को स्व-वाणी में खूब लिखा और गाया है-

श्रीवृन्दावन मधि दुम जेते।

तुलसी विविध रूप धरि तेते।।

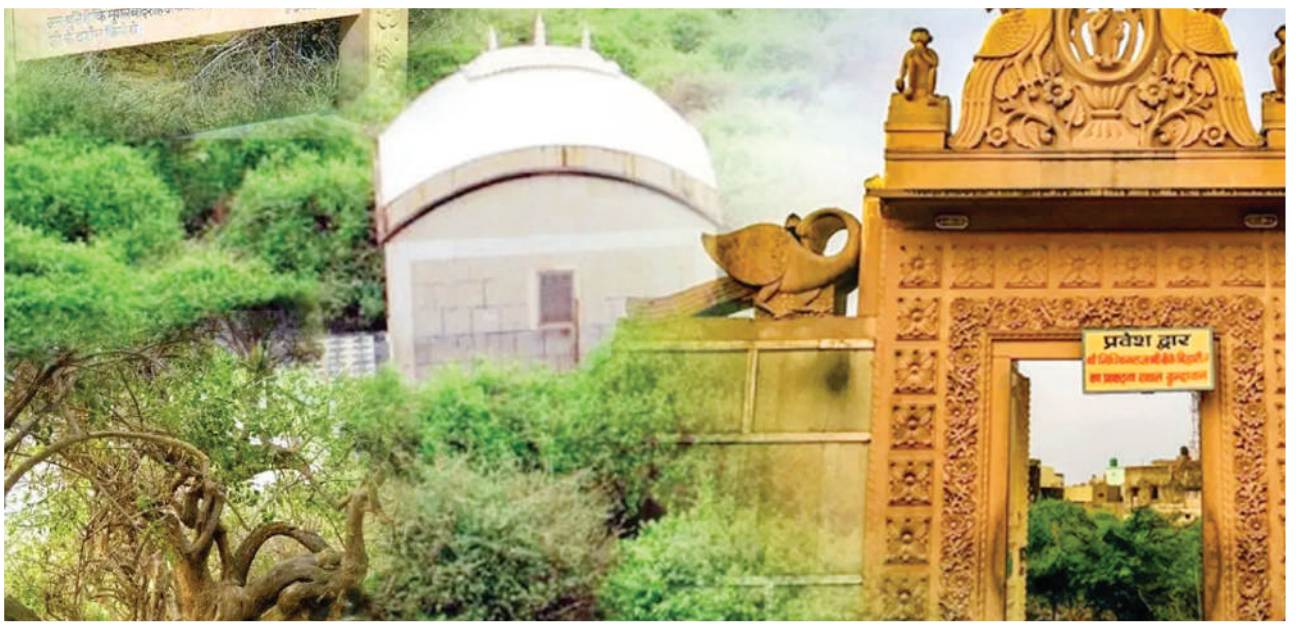
(निजमत सिद्धान्त-किशोरदास, आचार्य खण्ड)

वृन्दा-विपिन के साधकों के हाथ में सुशोभित बाँकी या लकुटि आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव-बोध कराती है। आज भी यहाँ विभिन्न प्रस्तर तथा कागज के पुरा अभिलेखों से 'कुंज' शब्द की व्याप्ति को समझा जा सकता है। यह वन-सेवी साधक-आचार्यों द्वारा प्रदत्त संस्कार ही है कि यहाँ देश की विभिन्न रियासतों द्वारा बनवाये गये मंदिरों को, उस 'कुंज' शब्द से सम्बोधित किया गया, जिसके मायने शब्दकोश में लता-वृक्षावलियों से आच्छादित सुरम्य स्थल के रूप में दर्शित हैं। वृन्दा के इस वन के प्रति भक्त वृन्दा का भाव यही था -

**गावत वृन्दा विपिन गुन, स्वयं लाड़िली लाल।
सुखद लता फल फूल दुम, अद्भुत परम रसाल।।**

(वृन्दावन सत लीला-ध्रुवदासजी)

वृन्दावन के प्रति साधक-आचार्यों की निष्ठा से जुड़े संदर्भ स्वयं को मूर्त-अमूर्त रूपों में बहुविध अभिव्यक्त करते हैं। ग्रीष्म रितु के दौरान यहाँ मंदिरों में बनने वाले भव्य कलात्मक फूल बंगले तथा पुष्प कली शृंगार इस भाव को दर्शाते हैं। यहाँ फूल बंगलों की सजावट का मात्र कलात्मक प्रस्तुतिकरण ही नहीं अपितु लता-वृक्षावलियों पर आधारित पदों का लेखन तथा रागबद्ध पारम्परिक गायन हमें आज भी वृन्दा-विपिन के प्रति उस अद्वितीय भाव की स्मृति कराता है, जिसे वन-सेवी आचार्यों ने श्रद्धा की डोर से सतत सिंचित किया। ब्रज-वृन्दावन में वृन्दा के पवित्र काष्ठ से निर्मित कंठी माला वैष्णव साधकों की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। इसी क्रम में तुलसी की जड़ की पवित्र मृत्तिका सहित सेवा-विधान में तुलसी-दल जैसी मान्यतायें यहाँ वृन्दा के प्रति अगाध श्रद्धा दर्शाने वाली हैं। दुखद है कि मन्दिरों का नगर कहे जाने वाले वृन्दावन में आज, उस वन देवी वृन्दा का एक भी मन्दिर नहीं, जो वन-उपासक संत-आचार्यों की जीवन पद्यति का मुख्य आधार रही है। साधक जन युगल स्वरूप राधाकृष्ण की हेतु भक्ति में रत होने से पूर्व, वन देवी वृन्दा को प्रसन्न करने के निमित्त उनसे यहाँ स्थायी निवास हेतु निवेदन करते थे।



वृन्दावन के विषय में जानकारी देने वाले पुरा सन्दर्भ बताते हैं कि 16वीं से 18वीं सदी के बाद तक यहाँ विभिन्न स्थलों पर वृन्दा देवी के मन्दिर भी थे। कभी लता-पताओं से आच्छादित वृन्दावन आज सीमेंट, कंक्रीट की इमारतों से घिरा पड़ा है। यह प्रक्रिया वर्तमान में तीव्रता से जारी है। अगर वृन्दा के इस विपिन की पहिचान बनाये रखनी है, तो हमें वन-उपासकों द्वारा प्रदत्त उस दृष्टि से गुजरना होगा, जहाँ यह भाव संस्कारों में रहा है। वे पवित्र संस्कार जिनका सुफल आज भी हमें यहाँ निधुवन, सेवाकुंज, किशोरवन, रसिकबिहारी मंदिर, मदनटेर (ऊँची ठौर) एवं टटिया स्थान आदि के रूप में पुराने वृन्दावन की स्मृति दिलाता है। वृन्दावन के मंदिरों में यह परम्परा आवश्यक रूप से रही, जो भी मंदिर बने उन्होंने पृथक से बाग-बगीचे अवश्य बनाये। वृन्दावन में आज घनी आबादी में बदल चुके ऐसे कुछ स्थल गोविन्दबाग, गोपीनाथबाग और बागबुन्देला आदि इस संदर्भ में साक्ष्य उपस्थित करते हैं।

पूर्व थे वृन्दादेवी के कई मन्दिर -

वृन्दावन में वृन्दादेवी के मन्दिरों की जानकारी पुरा ग्रंथों से मिलती है। यहाँ गोविन्ददेव मंदिर में वृन्दादेवी मंदिर के साथ ही वृन्दावनस्थ छीपीगली में गूदर भूधरदास बाबा की वृन्दादेवी तथा सेवाकुंज के समीप भी वृन्दादेवी का मंदिर होने की जानकारी पुरा संदर्भों से मिलती है। सेवाकुंज के समीप वृन्दादेवी मंदिर का उल्लेख तत्कालीन ब्रिटिश जिलाधिकारी एफ.एस.ग्राउस द्वारा रचित मेमोयर में मिलता है। इसी क्रम में ब्रजयात्रा की विभिन्न पोथियों में वंशीवट परिक्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर महादेव के समीप वृन्दादेवी के मन्दिर की जानकारियाँ भी मिलती हैं। मान्यतानुसार

पूर्व में श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभजी के द्वारा वृन्दादेवी के श्रीविग्रह को वृन्दावन में स्थापित किया गया था। 16वीं सदी के दौरान वृन्दावन के ब्रह्मकुण्ड से श्रीरूप गोस्वामीजी ने वृन्दादेवी के विग्रह का प्राकट्य किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में वृन्दावन का गोपेश्वर मन्दिर परिक्षेत्र संभवतः लोक सम्बोधन में वृन्दावनस्थ ब्रह्मकुण्ड तथा गोविन्ददेव तक के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो। जिस कारण ब्रजयात्रा के लिखित विवरणों में गोपेश्वर महादेव के साथ ही पुनः-पुनः वृन्दादेवी का उल्लेख आया है। पुराने समय में ब्रह्मकुण्ड, गोविन्ददेव मन्दिर के ही आहते में हो तथा प्राकट्योपरान्त वृन्दादेवी जी की सेवा-पूजा इस स्थल (योगपीठ) पर की जाती रही हो। इसी कारण इसे ब्रजयात्राओं में गोपेश्वर महादेव के समीप इंगित किया जाता रहा। जो भी हो यह शोध का विषय है कि गोपेश्वर महादेव के समीप पृथक से वृन्दादेवी का मन्दिर था, या ये वही वृन्दादेवी है, जो रूप गोस्वामीजी के द्वारा प्रकटित और गोविन्ददेव मन्दिर प्रांगण में सेवित रहीं।

वृन्दावन के गोविन्ददेव मन्दिर में स्थित वृन्दादेवी की ख्याति विभिन्न संदर्भों से उद्घाटित है। यहाँ वृन्दादेवी का भव्य मन्दिर हुआ करता था। औरंगजेब के शासनकाल में जब यहाँ के प्रायः श्रीविग्रह ब्रज से बाहर गये, उस दौरान वृन्दावन के प्रसिद्ध गोविन्ददेव मन्दिर में विराजित वृन्दा देवी का श्रीविग्रह भी यहाँ से ले जाया गया। संदर्भ बताते हैं जयपुर महाराज के निर्देशन में श्रीविग्रहों को जयपुर ले जाने की तैयारी हुई। मार्ग में पड़ाव ब्रजस्थ काम्यवन में हुआ, जिसे आदि वृन्दावन भी कहा जाता है। कहते हैं यात्रा को आगे बढ़ाने के लिये श्रीविग्रहों को पुनः रथ में विराजित कराने की तैयारी हुई, गोविन्ददेव जी को

बैठाया गया। उस दौरान काफी प्रयासों के बाद भी वृन्दादेवी का रथ आगे की ओर न बढ़ा। वह वृन्दावन से बाहर नहीं जाना चाहती थीं। काम्यवन भी आदि वृन्दावन है, उन्होंने राजा को स्वप्नादेश दिया, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। तभी से वृन्दादेवी काम्यवन में भक्तों को दर्शन लाभ दे रही हैं। प्रश्न यह भी है तीर्थ अनेक हैं, फिर वृन्दावन का ही इतना महात्म्य क्यों? बात विस्तार की है, पर संक्षेप में समझें तो यह वो दिव्य स्थली जहाँ समस्त संसार को भक्ति प्रदान करने वाली भक्तिमाता और मोक्षदायिनी मुक्ति भी स्वयं का मंगल प्राप्त करती हैं। ऐसे वृन्दा-विपिन की महत्ता का कहना ही क्या। संत-आचार्यों ने इस मर्म को समझा, वह जानते थे युगल सरकार की नित्य विहार स्थली वृन्दा-विपिन ही, उनका नित्य सानिध्य प्राप्त करने का उचित स्थल है। वास्तव में वन देवी की कृपा से इन साधकों ने वृन्दा-विपिन को जिया। वृन्दावन को जीने वाले साधकों की इस पवित्र भूमि से जुड़ी अभिव्यक्तियाँ स्वयं को एक समृद्ध लिखित परम्परा के रूप में स्थापित करती हैं।

वर्तमान वृन्दावन की स्थिति बिल्कुल उलट है, न वृन्दा है और न वह वृन्दा-विपिन, न वृन्दा द्वारा पालित उन दक्ष-विचक्षण शुकों का मधुर कलरव है, जो कभी वन देवी के संकेत पर इस पवित्र वन की शोभा वृद्धि करते थे। स्वयं वृन्दा के वे मंदिर भी इस वृन्दावन में अब नहीं दिखते, जिनके विवरण पुरा-ग्रंथों से सुलभ हैं। वर्तमान परिदृश्य में उस दिव्य वृन्दावन का वह वैभव हमें प्रथम दृष्टया भले ही दर्शित न हो, पर आज जब भी हम वन-सेवी आचार्य-साधकों की वाणियों के निकट होते हैं, तो वह वृन्दावन आज भी सहज प्रत्यक्ष होता है। ■

-शोध अधिकारी, वृ.शो.सं.



75
आजादी का
अमृत महोत्सव



मुफ्त इलाज - मुफ्त दवाएं बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाएं



गोरखपुर
एवं रायबरेली
में एम्स का
संचालन

एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज की ओर अग्रसर

65 मेडिकल कॉलेज संचालित
22 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन

आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में

9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति परिवार
₹5 लाख का चिकित्सा बीमा कवर

250 सीएचसी पर टेलीमेडिसिन सेवाएं व
361 सीएचसी पर टेली रेडियोलॉजी सेवाएं

लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय

गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय

अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस

4,720 एम्बुलेंस का संचालन

552 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का हेल्थ वेलनेस सेंटर के
रूप में विकास

सभी सीएचसी एवं पीएचसी में स्थापित हो रहे **हेल्थ एटीएम**

एमबीबीएस में **3,988**, पीजी में **1,747**,
नर्सिंग में **7,000** एवं पैरामेडिकल में **2,000** सीटों की वृद्धि

चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में
12 करोड़ मरीजों का उपचार



स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार - डबल इंजन की सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश



नये चेहरों पर भरोसा जता कर भाजपा ने

राजनीति में कर दिया बड़ा उलटफेर

भाजपा ने न केवल नए चेहरों पर भरोसा किया है बल्कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों को भी उनकी जमीन दिखाने की कोशिश की है, इस तरह की राजनीति के दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, वहीं राजनीति में नये चेहरों के आने से ताजगी का अहसास किया जा सकता है।

ललित गर्ग

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में ऐतिहासिक जीत के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद पर चौकाने वाले नामों के फैसले लेकर सबको चकित किया है, उनसे स्पष्ट है कि यह पार्टी राजनीति की नयी परिभाषा गढ़ने के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं को भविष्य के नेता बनाने के लिये तत्पर है। पार्टी एवं विशेषतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम जनता को संदेश दे रहे हैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी में एक दिन ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जिस तरह मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है उससे यह भी साफ करने की कोशिश की गई है कि कोई भी अपनी लोकप्रियता का ढिंढोरा पीटकर और विधायकों को अपनी जेब में रखने का भ्रम दिखा कर मुख्यमंत्री बन सकता है तो भाजपा आलाकमान उसकी यह दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा में गढ़ी जा रही नयी राजनीतिक परिभाषाएं ही उसके प्रचंड जीत का आधार बन रही है। भाजपा नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं की जाती, बल्कि सबका साथ, सबका विकास के आधार राजनीति धरातल को मजबूती दी जाती है। सबके अस्तित्व को नकार कर सिर्फ स्वयं के होने की प्रस्तुति कभी नेतृत्व एवं कर्तृत्व के कद को ऊंचाई दे सकती। भाजपा ने न केवल नए चेहरों पर भरोसा किया है बल्कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों को भी उनकी जमीन दिखाने की कोशिश की है, इस तरह की राजनीति के दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, वहीं राजनीति में नये चेहरों के आने से ताजगी का अहसास किया जा सकता है। राजनीति किन्हीं नेताओं की बपौती नहीं है, यह बात मोदी जैसे नेता ही सिद्ध कर पाये हैं। वरना भारतीय राजनीति में परिवारवाद, धन एवं ताकत का बोलबाला रहा है, जमीन से जुड़े लोग तो राजनीति से घबराने लगे थे। लेकिन भाजपा की राजनीति ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। अनेक विधायकों की उम्र बीत जाती है मुख्यमंत्री पद का इंतजार करते, पर राजस्थान में भाजपा ने पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक ऐसा संदेश दिया है, जिसका असर पार्टी में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक एक खुशखबरी की तरह पहुंचा है। ऐसे फैसले कम होते हैं, पर जब होते हैं, तब लोकतंत्र और उसकी जमीनी राजनीति के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और अपने वास्तविक एवं आदर्श स्वरूप को आकार देने का पात्र बनता है। मोदी ने अपने नाम पर प्रादेशिक चुनाव लड़कर एवं जीतकर एक नयी प्रकार की राजनीति को विकसित करने का धरातल तैयार कर दिया है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजनीति में अब पीढ़ी परिवर्तन का बिगुल बज गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बारी-

तीनों ही सीएम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं...

नरेन्द्र मोदी के साथ अमित शाह ने भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ वर्षों में यही संदेश दिया है कि वे पार्टी की मजबूती के लिए बूथ लेवल पर मेहनत करेंगे तो समय आने पर उनको उनका मेहनताना दिया जाएगा। भले ही वह विष्णुदेव साय जैसा जमीनी कार्यकर्ता हों। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा भी था, विष्णुदेवजी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को भाजपा आपके सामने लाई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाकर अमित शाह ने सचमुच उन्हें बड़ा आदमी बना दिया है। इसी तरह की सोच की वजह है कि भाजपा केंद्र में भी 2014 से लगातार सत्ता में बनी हुई है और राज्य स्तर पर भी अपनी धमक दिखा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए चुने गए नए नाम 2024 की रणनीति के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए मोदी-शाह फॉर्मूला एकदम साफ है कि उसके नेताओं की साफ-सुथरी छवि होनी चाहिए, आरएसएस से संबंध होना चाहिए, युवाओं को आगे लाने की कोशिश होनी चाहिए, लीडरशिप में नई पीढ़ी को उतारना मकसद हो, सीएम और 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला हिट है एवं जातियों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है, जिसके दम पर भाजपा राज्यों में अपनी पकड़ बनाकर रखती है और केंद्र में जीत के लिए रास्ता साफ करती है। अगर आप तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को देखें तो, उनके चुने जाने की पहली वजह है साथ सुथरी छवि। तीनों ही सीएम पर किसी तरह का कोई गंभीर आरोप नहीं है, जो पार्टी के लिए मुसीबत बन सके। तीनों ही सीएम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं।

बारी सत्ता संभालते आ रहे थे और सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, ऐसे में उनको निराशा हाथ लगी है। अब व्यक्तिवादी राजनीति का युग समाप्ति की ओर अग्रसर है, यह भारत में राजनीति को अधिक स्वच्छ, आदर्श एवं दमदार बनायेगा। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान ही यह साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति को भी मोदी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जिसे नवनिर्वाचित विधायक पसन्द करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। भाजपा ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा आगे रख कर लड़े थे और स्वयं मोदी ने अपनी गारंटी देकर लोगों से वोट मांगे थे। तीनों में से किसी एक राज्य में भी संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश नहीं की गई थी। इससे चुनाव प्रचार के दौरान ही यह साफ हो गया था कि इस बार मुख्यमंत्री के नाम न केवल चौकायेगे बल्कि सुखद अहसास का सबब भी बनेंगे। राजस्थान में इसके कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे तो भाजपा इस तरह के चकित करने वाले फैसले पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही चौकाने एवं चमत्कृत करने वाले फैसले लिए। भाजपा ने इन तीनों राज्यों की कमान केवल नए चेहरों को ही नहीं थमाई, बल्कि उन नेताओं को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया, जो अपेक्षाकृत युवा हैं और पार्टी की विचारधारा से गहरे से जुड़े रहने के साथ जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं। महिला नेतृत्व को भी आगे लाया गया है। ऐसे नेताओं को आगे करके भाजपा ने यही संदेश दिया कि वह एक ऐसा दल है, जिसके सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और लगन से उच्च पद पर

पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई संदेश न तो परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली कांग्रेस दे सकने में समर्थ है और न ही क्षेत्रीय दल। अनेक नये प्रयोगों के माध्यम से भाजपा खुद को मजबूत बना रही है एवं राजनीति की विसंगतियों एवं विडम्बना को दूर करने की गाथा भी लिख रही है। उसने इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्रियों के चयन में समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा। इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरों के जरिये भाजपा ने जिस तरह अपने सामाजिक समीकरण मजबूत किए, उससे उसके विरोधियों के इस तरह के आरोपों की हवा निकल गई कि वह अमुक अमुक वर्ग की उपेक्षा करती है। दलित, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के नेताओं को उचित प्रोत्साहन देकर भाजपा ने यह और अधिक अच्छे से रेखांकित किया कि वह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा न केवल मतदाताओं के दिलों को जीतने के मामले में अन्य दलों से कहीं अधिक आगे नजर आने लगी है, बल्कि नेताओं की नई पीढ़ी को तैयार करने और उन्हें अवसर देने के मामले में भी उसने नई लकीरें खींची है। स्पष्ट है कि इससे उसके सामान्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का कहीं अधिक संचार हुआ है और मतदाता भी उत्साहित एवं हर्षित दिख रहा है। जहां राजनीति दलों के नेताओं एवं मतदाताओं की निष्ठा का समन्वय नहीं होता, वहां उनकी मानसिकता में या तो दब्युपन, कायरता, हीनता, भय, तनाव पैदा हो जाती है या फिर वे अति लापरवाह, निस्संकोच, मुंहफट, ढीठ हो जाते हैं, ऐसी स्थितियों में असंतोष, विरोध, विद्रोह ही पनपते हैं। ■

अब कौन पहुंचायेगा सरकारी संपत्ति को नुकसान



जिस बात का देश से प्रेम करने वाले हरेक नागरिक को विगत दशकों से इंतजार था, वह अब हो गई है। अब किसी आंदोलन के दौरान कथित आंदोलनकारी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि नुकसान पहुंचाया तो उन्हें सख्त सजा होगी। हमारे यहां सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने वाले आमतौर पर सरकारी बसों, इमारतों, रेलों और दूसरी सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेशर्मी से तोड़ते रहे हैं। कहना न होगा आजाद भारत में इस कारण से सत्तर सालों में अरबों-खरबों रुपये का नुकसान हुआ। जिन्होंने नुकसान किया उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। वे दशकों से मौज करते रहे।



अजय शर्मा

उनमें से कई बड़े नेता भी बन गए। पर अब आगे किसी ने सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के अपडेटेड वर्जन में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसमें 'आतंकवादी कृत्य' में देश की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता पर हमले भी शामिल किये गये हैं। संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में सदन में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने नए विधेयकों को पेश किया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 113(1) में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा या हरकत करता है, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान या खतरा पैदा होता है, या आतंकी घटना की मंशा रखता हो, आतंकी हमले करता हो, इसके लिए बम, हथियार, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियार और जहर आदि का इस्तेमाल करता हो, जिससे जान-माल का नुकसान हो तो ऐसे मामले में दोषी शख्स को उम्रकैद या फांसी की सजा तक हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 113(5) में कहा गया है कि अगर कोई शख्स भारत की रक्षा परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो या अन्य तरह की सरकार की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो तो वह आतंकवाद यानी टेरर एक्ट माना जाएगा। इसी कानून की धारा 113(बी) में कहा गया- अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे या पब्लिक फंक्शनरी पर हमला करता है या अगवा करता है या ऐसी मंशा रखता है तो ऐसे मामले को भी टेरर एक्ट माना जाएगा। इससे मौत होने पर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान है।

आपको याद होगा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रुख भी अख्तियार कर लिया। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने

भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बसें और दूसरी गाड़ियां जला दीं थीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर नाखुशी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को बसें जलाने का अधिकार किसने दे दिया? कोर्ट ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर उतरने का अधिकार तो है लेकिन, वो अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे तो कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा।

अक्सर विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। कभी बसें जला दी जाती हैं, कभी ट्रेनों पर पथराव होता है, कभी सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़ होती है, तो कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का नुकसान किया जाता है। ये सवाल बार-बार पूछा जाता था कि अगर विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब स्थिति साफ हो गई है। अब किसी ने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहना ना होगा कि विरोध प्रदर्शन के कारण भारतीय रेलवे को तो हमेशा बलि का बकरा ही समझा जाता है। रेलवे को पिछले तीन सालों में लगभग 262 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है और रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान 2022 में हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते तीन सालों में यानी कि 2020, 2021 और 2022 में भारतीय रेलवे को 1.78, 0.68 और 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण हुआ है। 2022 में भारतीय सेना द्वारा सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी जिसका देश के कई राज्यों में काफी विरोध हुआ था। उस समय रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई थीं। वहीं कई ट्रेनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। दरअसल सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून पहले भी था। उसे सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 कहते थे। ■

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते तीन सालों में यानी कि 2020, 2021 और 2022 में भारतीय रेलवे को 1.78, 0.68 और **259.44** करोड़ रुपए का नुकसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण हुआ है।

नए और सख्त कानून की थी दरकार

इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती थी। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान था। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता था। पर पुराना कानून कमजोर पड़ रहा था या कहे कि उसका असर नहीं हो रहा था। इसलिए नए और सख्त कानून की दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट को भी हमेशा लगता रहा कि इस मामले में और भी उपाय किए जाने की जरूरत है। 2007 में सार्वजनिक संपत्ति के भीषण नुकसान की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस वक्त हिंसक विरोध प्रदर्शन, बंद और हड़ताल में सरकारी संपत्ति का खूब नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कानून में बदलाव के लिए दो कमिटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और सीनियर वकील फली नरीमन को कमेटियों का प्रमुख बनाया गया था। 2009 में इन दोनों कमेटियों की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। कहना ना होगा कि अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि सरकारी संपत्ति से तोड़-फोड़ करने से पहले देश के दुश्मन दस बार सोचेंगे।

व्यर्थ नहीं गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का

बलिदान

अदालती फैसले ने नेहरू और शेख को गलत साबित कर दिया

नीरज कुमार दुबे

इसके अलावा अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 को लेकर नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलत फैसले किये थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सही फैसला किया है। अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। देखा जाये तो यह फैसला सिर्फ मोदी सरकार की बड़ी जीत नहीं है बल्कि इस फैसले के जरिये भाजपा ने विचारधारात्मक रूप से भी एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। हम आपको याद दिला दें कि जनसंघ के जमाने से ही भाजपा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रति संकल्पबद्ध रही है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते।' उस नारे को हकीकत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। इसके अलावा अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 को लेकर नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलत फैसले किये थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सही फैसला किया है। अदालत का फैसला यह भी दर्शाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यदि देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिये गये ऐतिहासिक फैसले को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि कश्मीर को लेकर महाराजा हरि सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही थे तथा नेहरू और शेख अब्दुल्ला की नीतियाँ गलत थीं। उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यदि भारतीय संविधान देश के चार करोड़ मुसलमानों के लिए

अच्छा है तो जम्मू-कश्मीर के 35 लाख मुसलमानों के लिए कैसे गलत हो सकता है? 370 को समाप्त हुए साढ़े चार साल हो गये और जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों ने इस दौरान विकास और तरक्की का जो नया दौर देखा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि विशेष प्रावधान उनके जीवन में एक अवरोधक की तरह था। देखा जाये तो शेख और नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भारतीय संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़खानी की गयी थी जिसके चलते दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को अलगाववाद और आतंकवाद झेलना पड़ा। साथ ही, अनुच्छेद 370 मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए एकदम स्पष्ट कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने एक अस्थायी प्रावधान को 70 साल तक स्थायी बनाये रखा था? हम आपको बता दें कि संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 है जिसका शीर्षक है- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसमें कुल 36 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 370 के मार्जिनल नोट में स्पष्ट लिखा है- जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान। इसके अलावा विशेष शब्द आर्टिकल 371 के संबंध में जोड़ा गया था वह भी साल 1962 में। देखा जाये तो असली समस्या नेहरू और शेख के बीच हुआ राजनीतिक समझौता थी, जिसे 1952 का दिल्ली समझौता कहा जाता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह कोई औपचारिक समझौता नहीं बल्कि दो राजनेताओं के बीच की सहमति थी। खास बात यह है कि इस सहमति का हस्ताक्षरित दस्तावेज आज तक उपलब्ध

नहीं है। बहरहाल, जहाँ तक विचारधारा के स्तर पर संघ परिवार की कामयाबी की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश हित में तो तमाम कदम उठाये ही साथ ही अपने संगठन की मूल विचारधारा पर आधारित दो बड़े मुद्दों को हल करने के प्रति भी सजगता दिखाई। दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप प्रदान कर दिया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की ओर से नवंबर 2019 में अयोध्या संबंधी विवाद का हल निकाले जाने के बाद 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रख कर दूसरा संकल्प सिद्ध किया। अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जायेगी और इसी के साथ सैंकड़ों वर्षों से देखा जा रहा सपना पूरा होगा। देखा जाये तो विचारधारा के आधार पर संघ परिवार का एकमात्र बड़ा संकल्प 'समान नागरिक संहिता' को देश में लागू करना बचा हुआ है। भाजपा शासित राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं और केंद्रीय विधि आयोग भी इस मुद्दे पर देशवासियों की राय ले चुका है इसलिए कहा जा सकता है कि यह संकल्प भी जल्द ही सिद्ध होगा। ■

With Best Compliments from



ECONOMIC TRANSPORT Co.

**C/o Superstar Leasing Financing Ltd.
Gandhi market, Fazal ganj, Kanpur
(Fleet Owner & Transport Contractor)**

Branches

Kanpur, Noida, Delhi, Gurgaon



संसद में छोड़े गये 'पीले रंग' में छिपे 'काले उद्देश्य' का

पता लगाना बेहद जरूरी है

आरोपियों का हमले की बरसी के दिन 'संसद अटैक-2' का संदेश देना निश्चित रूप से बेचैन करता है। पीले रंग में छिपे काले संदेश को समझा होगा। दुश्मन अंदरूनी है या बाहरी? उन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। प्रतीत ऐसा होता है कि आरोपी सिर्फ मोहरा मात्र हैं।

डॉ. रमेश ठाकुर

शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भारतीय संसद के अंदर शायद कुछ बहुत बड़ा होना मुकर्रर था क्योंकि 22 बरस पहले आतंकवादियों द्वारा दिया एक नासूर जख्म जो प्रत्येक 13 दिसंबर की तारीख के दिन याद करके हरा हो जाता है। खैर, गनीमत ये समझें कि संभावित घटना 'पीले रंग' तक ही सीमित रही, वरना कुछ 'काला' भी हो सकता था। 13 तारीख जैसे भी संसदीय परंपरा के लिए 'काली तारीख' ही है। केंद्र सरकार इस अधूरी घटना को हल्के में कतई न ले। नहीं, तो पीले रंग में छिपी ये

संदेशवाहक घटना कभी भी पूर्ण घटना में तब्दील हो सकती है। इतना सतर्क हो जाना चाहिए कि दुश्मन घात लगाए बैठा है इसलिए अभी से इस तस्वीर को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आरोपियों की बुनी साजिश की जड़ तक घुसना होगा? उनका मकसद दहशत फैलाना मात्र था या कुछ और? फिलहाल ऐसे तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। पर, अब्वल तो इस घटना को घोर लापरवाही और सुरक्षातंत्र की नाकामी ही कहेंगे। चाकचौबंद सुरक्षा-व्यवस्था से कहां चूक हुई, इसकी भी समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

बहरहाल, संसद तो नई-नवेली है, जिसे

अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस बताया जाता है। लेकिन घटना जिस अंदाज में घटी उससे साफ पता चलता है कि साजिश की तासीर कुछ और थी। आरोपी सामान्य हैं या असामान्य प्रवृत्ति के, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर, लोग अंदिशा ऐसा भी लगा रहे हैं कि कहीं 22 साल पहले 13 दिसंबर को जो घटना संसद में घटी थी ये उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं? या फिर उसका पार्ट-2 की चेतावनी है। इस लापरवाही की जवाबदेही किसकी हो, ये बिना देर किए सुनिश्चित हो। एक थ्योरी ये समझ में नहीं आती कि आखिर शीतकालीन सत्र को चले कई दिन हो चुके हैं।

पर, हरकत संसद हमले की बरसी के दिन ही क्यों होती है? अर्चभित कर देने वाली बात एक ये भी है कि आरोपियों ने भगत सिंह के स्टाइल को क्यों कॉपी किया? पीला धुआ फैलाकर, नारे लगाना, तानाशाही से मुक्ति मिले? आखिर ये सब किस ओर इशारा करता है। कौन है घटना के पीछे, उसे सामने लाना ही होगा और आरोपी ने जो तानाशाही से आजादी के नारे लगाए हैं उसके निहितार्थ भी सार्वजनिक होने चाहिए।

आरोपियों का हमले की बरसी के दिन 'संसद अटैक-2' का संदेश देना निश्चित रूप से बेचैन करता है। पीले रंग में छिपे काले संदेश को समझा होगा। दुश्मन अंदरूनी है या बाहरी? उन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। प्रतीत ऐसा होता है कि आरोपी सिर्फ मोहरा मात्र हैं। मास्टर माइंड कोई और ही है? जब से नई संसद में सत्र और संसदीय कार्य शुरू हुए हैं। संसद सदस्य अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चित और बेखबर हैं। क्योंकि संसद की सुरक्षा सेफ्टी मानकों के लिहाज से अत्याधुनिक बताई जाती है। संसद की एक-एक ईट और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा पहरा बिछा हुआ है। खुदा न खास्ता इंसानी सुरक्षा तंत्र से अगर कोई चूक भी हो जाए, तो पूरी बिल्डिंग तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। कोई संदिग्ध क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर, अब इन मौखिक और कागजी सुरक्षा व्यवस्था पर संसद सदस्यों को एतबार नहीं रहा। क्योंकि उन सभी को धता बताते हुए आरोपी विजिटर बनकर आसानी से भीतर घुस गए और अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया।

गनीमत ये समझें कि घटना के दौरान आरोपियों के हाथ में सिर्फ 'स्मोक बम' ही थे, अगर असलहा-वगैरह होता तो वो इस्तेमाल भी कर सकते थे। क्योंकि जब वो सुरक्षा तंत्र की आंखों में धूल झोंककर आपत्तिजनक वस्तुएं अंदर ले जा सकते हैं तो बंदूक-बारूद क्यों नहीं? इसलिए घटना को सबसे पहले सुरक्षा चूक ही कहेंगे। जबरदस्त सुरक्षा पहरे को बेवकूफ बनाकर 'स्मोक बम' फेंककर संसद के भीतर आरोपी अफरा-तरफ़ी मचा देते हैं। बकायदा विजिटर बनकर संसद की कार्यवाही देखने पहुंचते हैं। दर्शक दीर्घा में करीब चार-पांच घंटे बिताते हैं और लंच से पहले अचानक छलांग लगाकर सांसदों की कुर्सियों तक जाते हैं। पीले रंग का 'स्मोक बम' फोड़ देते हैं। 'तानाशाही से आजादी' जैसे नारे लगाते हैं। ये पूरा वाक्या तकरीबन चालीस से पैंतालीस मिनट तला। सुरक्षाकर्मियों के पहुंचने से पहले दो सांसद हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर हिम्मत दिखाकर उन्हें दबोचते हैं और उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले करते हैं।

आरोपी मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर कार्यवाही देखने पहुंचे। वो झूठ बोल रहा है या सच? ये जानने के लिए उसका नार्की, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जरूर करवाना



क्या हुआ था?

संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में संधमारी की बड़ी घटना सामने आई थी। दोपहर करीब एक बजे जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के अंदर कूद गए और सांसदों की बैठने की जगह पर दौड़ते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने जूते में छिपाकर लाए 'केन' के जरिए पीले रंग का धुआं भी स्प्रे किया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया।

अब आरोपियों के बारे में जानिए

सदन में कूदने वाले दोनों आरोपियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के रूप में हुई। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम (42) और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे (25) के रूप में हुई है। चारों आरोपी संसद पहुंचने से पहले अपने सहयोगी विशाल के घर पर ठहरे थे। पुलिस ने विशाल को भी गुरुगाम से हिरासत में लिया था। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड की पहचान बिहार के रहने वाले और कोलकाता में नौकरी करने वाले ललित झा के रूप में की।

अब जानते हैं पूरा घटनाक्रम

2022 में ललित झा, सागर शर्मा (26) और मनोरंजन डी (34) मैसूर में मिले। उन्होंने देश का ध्यान खींचने के लिए संसद में घुसने की साजिश रची। बाद में नीलम और अमोल इसमें शामिल हो गए। सभी करीब चार साल से सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के संपर्क में थे। इसके बाद पांचों फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज से जुड़े।

चाहिए। अगर कोई गहरी साजिश है भी, जैसा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी दावा कर रहे हैं, तो उसे पता लगाने की दरकार है। संसद में सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। 22 वर्ष पूर्व हुए हमले की बरसी थी जिस पर सभी सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद रोजाना की भांति सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाते हैं। किसी को थोड़ा-सा भी अंदेश नहीं था कि नई संसद में भी कोई ऐसी भी हरकत कर सकता है। संसद सदस्य आश्वस्त थे कि नई संसद सुरक्षा मानकों के चलते अभेद्य है। बावजूद आरोपी चार नंबर गेट से विजिटर बनकर प्रवेश कर जाता है। क्या आरोपी 'स्मोक बम'

के जरिए कोई संदेश फैलाना चाहता था, ये फिर उसे मात्र पब्लिसिटी चाहिए थी। हालांकि ऐसे सभी सवालों की लंबी लिस्ट बनाकर स्थानीय पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ में लगी हैं। लेकिन विपक्षी दल किसी बड़ी घटना होने की आशंका जता रहे हैं। उनकी आशंकाओं को ध्यान में रखकर भी जांच करनी चाहिए, इसके अलावा उसी वक्त बाहर भी एक युवती-युवक तानाशाही से आजादी के नारे लगा थे, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। देशवासियों में ये संदेश बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं तो वो भला कैसे सुरक्षित होंगे। ■

क्या इतना आसान है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को भेदना

सबसे बड़ा सवाल है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या एक आम आदमी के लिए सदन के सबसे सुरक्षित हिस्से तक पहुंचना बहुत आसान है? सुरक्षा चूक के बाद अब सिक्योरिटी में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे।

अभिनय आकाश

संसद के अलावा भारत में ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां देश के सारे वीवीआईपीपीपी एक ही समय में एक ही जगह पर एकट्ठा होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें दोनों सदनों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सारे सांसद शामिल होते हैं। लेकिन संसद की कार्यवाही चल रही थी कि तभी दो लोग दर्शक दीर्घा से कूद पड़े। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अपने हाथ में कलर स्मोक लिया हुआ था जिससे पीला धुआ भी निकला। ये दोनों लोग कुछ नारे भी लगा रहे थे। वहां मौजूद सांसदों ने इन्हें पकड़कर पीटा है। इनके इरादे और अन्य जानकारियां पूछताछ के बाद धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नीलम और अनमोल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर भी रिपोर्ट ली गई है। लोकसभा सचिवालय ने 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा उल्लंघन मामले में 8 कर्मियों को निर्लंबित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या एक आम आदमी के लिए सदन के सबसे सुरक्षित हिस्से तक पहुंचना बहुत आसान है? सुरक्षा चूक के बाद अब सिक्योरिटी में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे।

संसद तक आम आदमी की पहुंच

हमारे देश की संसद में कोई भी आम आदमी जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी सख्त प्रक्रियाएं हैं। दरअसल, दो तरीके से संसद में प्रवेश मिल सकता है। पहला विजिट के लिए पास बनवाना। इस तरह के पास से संसद के अंदर म्यूजियम आदि दिखाया जाता है। इसके अलावा संसद में एक विजिट तब होती है जब संसद में सत्र चल रहा होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति संसद में जाकर लोकसभा की कार्यवाही सीधे देख सकता है। लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए भवन के अंदर एक दर्शक दीर्घा होती है। ये गैलरी लोकसभा में बॉलकोनी में बनी हुई है। यहीं ऊपर में आम लोग बैठते हैं। लोकसभा में एंट्री के लिए जो पास दिया जाता है वो एक सीमित वक्त के लिए होता है। इसी के अनुसार आम लोगों की एंट्री होती है। लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म लोकसभा की वेबसाइट या उसके रिसेशन ऑफिस से मिलता है। इस फॉर्म में नाम, स्थायी पता आदि की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन के इस फॉर्म को किसी भी सांसद से वेरिफाई करवाना होता है। ये सांसद आपके क्षेत्र से हो ऐसा जरूरी नहीं है। पास पर सांसद की मुहर और हस्ताक्षर होते हैं।

किसी भी विजिटर्स को परमिशन नहीं

लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन के बाद उठाए गए पहले



उपायों में से एक संसद में आगंतुकों के प्रवेश को निर्लंबित करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के महासचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और अगले आदेश तक आगंतुक परमिट जारी करने को निर्लंबित करने का फैसला किया। यह बात सामने आने के बाद सामने आई है कि घुसपैठियों में से एक को भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय से विजिटर्स पास मिला था। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों में से एक सिन्हा के निर्वाचन क्षेत्र मैसूर का रहने वाला है और वह अक्सर उनके कार्यालय आता था। अधिकारियों ने कहा है कि जब वे आगंतुकों का प्रवेश फिर से शुरू करेंगे, तो उन्हें चौथे द्वार से प्रवेश करना होगा और एक चार स्तरीय सुरक्षा प्रणाली यानी अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। वर्तमान में, आगंतुकों को तीन स्तरों पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है।



नए, बढ़े हुए सुरक्षा उपाय

संसद में आगंतुकों के प्रवेश को निर्लाभित करने के अलावा, अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी सुधार किया है। ऐसा कहा गया है कि दर्शक दीर्घा, जहां से दो घुसपैटिए लोकसभा कक्ष में कूदे थे, अब शीशे से बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा, गैलरी में पहली पंक्ति को खाली रखने, दूसरी पंक्ति से आगंतुकों को बैठाने पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा, हवाई अड्डों की तरह बॉडी स्कैनिंग मशीनें परिसर में स्थापित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग संसद परिसर में प्रवेश करते समय वस्तुओं को छिपा न सकें। यह कदम तब उठाया गया जब पता चला कि घुसपैठियों ने अपने जूतों में गैस कनस्तर छिपा रखे थे। संसद के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि प्रमाणित पत्रकारों और स्टाफ सदस्यों को अब उन्हें सौंपी गई अलग

प्रविष्टि का सख्ती से पालन करना होगा और उन्हें कठोर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसके अलावा, सांसदों के निजी सहायकों और कर्मचारियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सदन के अंदर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। सांसदों के मुताबिक कम से कम 150 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जानी चाहिए।

जांच पैनल गठित

गृह मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि बुधवार को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच पैनल का गठन किया गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया

है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, जांच समिति सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य शामिल हैं। जांच समिति संसद की सुरक्षा में संध के कारणों की जांच करेगी, खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ सौंपेगी, जिसमें संसद में सुरक्षा में सुधार के सुझाव भी शामिल होंगे। घटना के बाद बुधवार शाम को कई विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण की मांग की। सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि नई संसद सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं है और गृह मंत्री को "सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत प्रतिक्रिया देनी चाहिए।" ■

मालदीव के मन में क्या है ?

पहले सैनिकों को लौटाया, अब तोड़ा पीएम मोदी के साथ किया ये समझौता

अभिनय आकाश

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार से देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया। अब भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहने के बमुश्किल एक महीने बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने हाइड्रोग्राफिक पर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ न कुछ कड़वाहट देखी जा रही है। दरअसल, 2018 ये वो साल था जब भारत और मालदीव के संबंध सबसे ज्यादा बेहतर होने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह थे। मोहम्मद सालेह के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया फ्रस्ट नीति पर काम करते थे। भारत पर यकीन करते थे। भारत से हर तरह के सौदे करते थे। उस वक्त मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत थे। लेकिन इस साल हुए चुनाव में उनकी सत्ता चली गई। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा था कि भारत और मालदीव के संबंधों में खटास होगी। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू भारत को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके भारत विरोधी बयान भी कई बार सामने आ चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार से देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया। अब भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहने के बमुश्किल एक महीने बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने हाइड्रोग्राफिक पर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है।

कौन हैं मोहम्मद मुइज्जू ?

मुइज्जू ने इस साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव जीता और उनकी जीत देश में विदेशी शक्तियों की भूमिका को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच हुई है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप देश है, और लगभग 500,000 लोगों का घर है। करीब एक दशक से चीन उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है। यह अर्धदक्षिण एशियाई क्षेत्र सहित चीन के उदय और उसकी शक्ति के प्रक्षेपण के साथ मेल खाती है। लंबे समय से भारत



मालदीव को अपने क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता रहा है। मालदीव के ताकतवर पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने कई वर्षों तक भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। 2008 के चुनावों में उनकी हार के साथ, नए नेताओं के चुनाव अभियान में विदेश नीति एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई है। 2008 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के मोहम्मद नशीद ने जीत हासिल की। एमडीपी और उसके शीर्ष नेताओं, विशेषकर नशीद को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता था। जब अब्दुल्ला यामीन 2013 और 2018 के बीच राष्ट्रपति रहे तो भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी खराब हो गए। 2018 में सोलिह के सत्ता में आने के बाद ही नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों में सुधार हुआ। सोलिह लगातार भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और "इंडिया फ्रस्ट" नीति पर चल रहे थे। अपने चुनाव के बाद मुइज्जू ने कहा था कि उनके हिंद महासागर द्वीपसमूह देश में मौजूद सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

जल सर्वे समझौता खत्म

8 जून, 2019 को हस्ताक्षरित समझौता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव का दौरा किया। भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, अध्ययन और चार्ट रीफ, लैगून, समुद्र तट, महासागर का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। यह पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे नवनिर्वाचित

मालदीव सरकार, जिसने नवंबर में कार्यभार संभाला था, आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फि रजुल अब्दुल खलील ने कहा कि मुइज्जू सरकार ने 7 जून, 2024 को समाप्त होने वाले हाइड्रोग्राफी समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की शर्तों के अनुसार, यदि एक पक्ष समझौते को छोड़ना चाहता है, तो समझौते की समाप्ति से छह महीने पहले दूसरे पक्ष को निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। शर्तों के अनुसार, समझौता स्वचालित रूप से अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाता है। फि रजुल ने कहा कि भारत को सूचित किया गया है कि मालदीव समझौते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। माले के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मालदीव सरकार ने मुइज्जू प्रशासन के फैसले से वहां भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया है। मालदीव समाचार आउटलेट द सन के अनुसार, मुइज्जू ने अपने कैबिनेट से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। द सन ने फि रजुल के हवाले से कहा कि प्रशासन का मानना है कि इस तरह के सर्वेक्षण करने और ऐसी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने के लिए मालदीव की सेना की क्षमता में सुधार करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हाइड्रोग्राफी का काम 100 प्रतिशत मालदीव प्रबंधन के तहत किया जाएगा और केवल मालदीव के लोगों को ही जानकारी दी जाएगी। ■

ADVANCE GROUP OF GLASS INDUSTRIES

MANUFACTURERS AND EXPORTERS

*Handicraft Glass Art Wares *Lead Glass Tubing *Soda Lime
Glass Tubing *Fancy Glass Tumblers & Giftware Items*
Glass Lanterns Chimneys *Glass Inner For Vacuum Flasks
*Table Wares * Glass Bangles *Liquor Bottles *Perfume
Bottles *Biological Equipments *Thermo Ware Items
*GLS Lamp Shells

With Best Compliments For

PRADEEP KUMAR GUPTA
CHAIRMAN

ASSOCIATE CONCERNS

- * ADVANCE GLASS WORKS
- * ORIENTAL GLASS WORKS
- * OM GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
- * MODERN GLASS INDUSTRIES
- * ADARSH KANCH UDHYOG PRIVATE LIMITED
- * ADVANCE LAMP COMPONENT
& TABLE WARES PRIVATE LIMITED
- * GREEN ORCHID

HEAD OFFICE

105, Hanuman Ganj, Firozabad- 283203 (Uttar Pradesh) INDIA
TEL: +91 5612 221796, MOB: +91 9837 082 127, 9897 012 063
email: info@advanceglassworks.com
omglassworkspvtltd@gmail.com
website: www.advanceglass.in

डॉ. रामनरेश शर्मा

एहसान फरामोशी के मामले में जम्मू-कश्मीर के कुछ लोगों का कोई जवाब नहीं है। उनकी बार-बार भारत के प्रति घृणा सामने आती ही रहती है। यह तो तब है जब भारत सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। अब ताजा मामले को ही देख लें। राज्य के गांदरबेल में मौजूद 'शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी' के सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इन कश्मीरी छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने विगत 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार के बाद जमकर जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गए। छात्रों के ऊपर 'गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम' यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्हें अब दिन में तारे नजर आने लगेंगे। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए लोगों के लिए जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। अगर किसी के ऊपर इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो उसके लिए निचली अदालतों से जमानत लेना बेहद कठिन होता है। इन छात्रों की हरकत के बारे में एक गैर-कश्मीरी छात्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, तब उनकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों ने खुलेआम जश्न मनाया। इसकी वजह से वह और उसके बाकी साथी डर गए। डरे और सहमे छात्रों ने हॉस्टल में फोड़े जा रहे पटाखों को लेकर भी आपत्ति जताई। मगर कश्मीरी छात्र जश्न मनाते रहे। शिकायत के बाद पुलिस ने इन सातों कश्मीरी छात्रों को उनके हॉस्टल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए छात्रों की पहचान तौकीर भट, मोहसिन फारूक वानी, आसिफ गुलजार वार, उमर नजीर डार, सैयद खालिद बुखारी, समीर राशिद मीर और उबैद अहमद के रूप में हुई है। गिरफ्तार कश्मीरी छात्र 'जीवे जीवे पाकिस्तान' (पाकिस्तान जिंदाबाद) के नारे लगा रहे थे। हालांकि कश्मीर में यह कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त समय-समय पर सामने आने ही लगते हैं। हालांकि इनकी संख्या कोई बहुत तो नहीं है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां किसी का भी दिल पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कता है। जम्मू-कश्मीर के कुछ वे नेता भी उन पाकिस्तान के चाहने वालों के हक में खड़े हो जाते हैं जो विधायक या सांसद भी रहे हैं। जिन्होंने भारत के संविधान में अपनी आस्था की कसम भी खाई है। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया तो पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती को बहुत तकलीफ शुरू हो गई। उनका पाकिस्तान प्रेम सिर चढ़ कर सामने आ गया। उन्होंने गिरफ्तार छात्रों के लिए तत्काल पैरवी करनी चालू कर दी। वह पहले भी पाकिस्तान के साथ बेशर्मा के साथ खड़ी हुईं नजर आती ही रहती हैं। याद नहीं आता कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुंबई हमलों के

पाक परस्तों के साथ महबूबा का प्रेम तो देखो



गुनाहगारों को फांसी देने की भी कभी पाकिस्तान सरकार से मांग की हो। यह भी याद नहीं आता कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के घोर भारत विरोधी नेताओं जैसे शेख राशिद अहमद और फावद चौधरी की बयानबाजी पर कभी आपत्ति जताई हो। यह दोनों भारत पर एटमी हमला तक करने की धमकी देते रहे हैं। तब महबूबा मुफ्ती की जुबान सिल जाती है, जब वहां का कोई नेता भारत पर हमला करने की बातें करता है। जरा सोचिए कि जिस पाकिस्तान को सारी दुनिया आतंक का गढ़ मानती है, उसके प्रति महबूबा मुफ्ती का प्रेम कितना खुलकर सामने आ जाता है। उनकी इस घृष्टता की अनदेखी तो नहीं की जा सकती। क्या महबूबा मुफ्ती को पता नहीं है कि मुंबई हमलों के सारे के सारे हमलावर पाकिस्तानी थे? क्या वह मानती हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था? सारी दुनिया को पता है मुंबई में हमला पाकिस्तान में रहने वाले कठमुल्लों ने ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई की मदद से ही करवाया था। भारत ने उस हमले के तमाम पुख्ता साक्ष्य पाकिस्तान को दिए। पर महबूबा मुफ्ती ने उन भयावह हमलों के लिए कभी पाकिस्तान को नहीं घेरा। पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी माना था कि मुंबई में 2008 में हमला पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकियों ने ही किया था। शरीफ ने कहा था कि मुंबई में हुए बड़े आतंकी हमले

के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। क्या महबूबा मुफ्ती ने कभी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के क्रम में अपनी जान लेने वाले तुकाराम ओम्बले के परिवार से मिलने की इच्छा तक जताई? क्या वह उनका अपना नायक नहीं मानती है? खैर, अब देश जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान को चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आस्तीन के सांप हैं। इन्हें खदेड़ा जाएगा। इन्हें चुन-चुनकर मारा जाएगा। भारत बदल चुका है। अब अपने देश में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वालों की खैर नहीं है। जम्मू-कश्मीर में पहले भी पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी होती रही है। तब भी पुलिस ने कठोर एक्शन लिया था। तब भी महबूबा मुफ्ती या उनके जैसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के बचाव में आते रहे थे। इनका तर्क था कि 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने में बुराई ही क्या है? क्या उन्होंने पेरू जिंदाबाद कहा होता तो किसी को कोई एतराज होता? अब इन अक्ल के दुश्मनों से पूछ लो कि क्या अजमल कसाब को पेरू ने मुंबई में खून-खराबा करने के लिए भेजा था? क्या इन्हें याद नहीं है कि मुंबई में कसाब और उसके साथियों ने किस तरह से सैकड़ों मासूम हिन्दुस्तानियों को मौत के घाट उतारा था? अगर इससे भी उनका दिल खुश नहीं होता तो याद कर लीजिए कि करगिल में पाकिस्तान ने क्या किया था। ■

क्यों बेवजह पीटा गया निर्दोष मुस्लिम महिला को

पवन 'आगरी'

अभी कुछ दिन पहले की एक खबर ने हरेक लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले इंसान को उदास कर दिया होगा। खबर संभवतः आपने भी पढ़ ली होगी। अगर किसी कारणवश नहीं पढ़ी तो बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के जिला सीहोर में एक मुस्लिम महिला को उसके ससुराल वालों ने इसलिए बुरी तरह पीटा, क्योंकि; उसने भाजपा को हालिया विधानसभा चुनावों में वोट दिया था। उस महिला को पीटने वालों में उसका अपना देवर भी शामिल था। उसे जब पता चला कि उसके भाई की पत्नी ने भाजपा के हक में वोट किया है तो उसने अपनी भाभी को बुरी तरह से डंडों से मारा। उसका कुछ संबंधियों और पड़ोसियों ने भी साथ दिया। इसके बाद पीड़ित महिला न्याय के लिए कलक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और वहां आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। अब जरा बताइये कि भाजपा के खिलाफ इतनी नफरत कुछ लोगों के मन में क्यों है। देश का कोई भी नागरिक किसी भी दल के उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। ये अधिकार देश का संविधान सभी को देता है। तब किसी को भी इस बात के लिए तकलीफ क्यों हो रही है कि उसके परिवार में किसने फलां-फलां दल के पक्ष में मतदान क्यों किया। दरअसल भाजपा सरकार से कुछ कठमुल्लों को इसलिए नाराजगी है क्योंकि उसने (भाजपा) ने मुसलमानों में ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे अमानवीय परम्परा को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए। इन कठमुल्लों की घोर महिला विरोधी सोच को जहां से भी ललकारा जाता है, तो ये पागलपन पर उतरने लगते हैं, बेवजह हिंसक हो उठते हैं। मुझे याद आ रहा है जब कुछ समय पहले मुंबई में उन मुस्लिम महिलाओं के साथ भी इसी तरह मारपीट और धक्कामुक्की की गई जो ट्रिपल तलाक के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रही थीं। उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं कुछ सड़क छाप मुस्लिम नेताओं और उनके चेलों द्वारा। इन लफंगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली महिलाओं पर इस्लाम विरोधी होने तक का आरोप भी लगा दिया था। अब मध्य प्रदेश की ताजा घटना को देखिए। हैरानी की बात ये है कि कोई भी मुस्लिम संगठन या अपने को मुसलमानों का नेता कहने वाला उस महिला के साथ खड़ा नहीं हो रहा है जिसके साथ मारपीट की गई है। अपने को मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाली तीस्ता सीतलवाड़ ने उस दीन-हीन महिला के हक में कोई बयान तक नहीं दिया है। वे तमाम लेखक और कैंडल मार्च निकालने वाले बुद्धिजीवी भी नदारद हैं जो बात-बात पर दीन-हीन मुसलमान औरतों का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। भाजपा को हर वक्त बुरा-भला



कहने वाले यह तो अब जान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने अभी तक के शासनकाल में औरतों के हक में तमाम बड़ी योजनाएं लागू की हैं और करते ही चले जा रहे हैं। उनका लाभ मुसलमान औरतों को भी हो रहा है। क्योंकि, मोदी जी के शासन में जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव तो है ही नहीं। इसलिए मुसलमान औरतों की मोदी सरकार और भाजपा को लेकर राय बदली है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अधिकांश संबोधनों में महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर देते हैं। मोदी सरकार युवाओं के साथ-साथ महिलाओं के विकास पर भी जोर दे रही है। उसकी तीन योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती मिली है। पहले बात की शुरुआत उज्जवला योजना 2023 से ही करते हैं। प्रदूषण को कम करने व महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा उज्जवला योजना लॉन्च की गई। इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओं को निशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा है। जाहिर है, इस योजना से जिन औरतों को लाभ हो रहा है उनमें मुसलमान और ईसाई महिलाएं भी हैं। क्या जिन्हें उज्जवला योजना से लाभ होने लगा है वह मोदी सरकार का बिना वजह विरोध करेंगी? अब बात करें फ्री सिलाई मशीन योजना की। इस योजना के अंतर्गत देश की तमाम महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, जिसके जरिए महिलाएं आसानी से घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकती हैं और जीवन का गुजर-बसर कर सकती हैं। अब मोदी सरकार की सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 'सुमन योजना' की बात कर लें। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को ही की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात

शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं इस योजना के जरिए सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पहले चार बार मुफ्त जांच का अधिकार है। इसके अलावा प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और प्रसव के बाद 6 महीने तक मां और बच्चे को निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी। जाहिर है, इन तमाम युगांतकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान औरतों को भी तो हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की पहल पर मुसलमान औरतों को तीन तलाक से मुक्ति मिली। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आया। इसने मुसलमान औरतों को तीन तलाक की बर्बर कुप्रथा से मुक्ति दिलवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तीन तलाक पर रोक लगा दी। कहते हैं कि हैं कि न्याय अंधा होता है। वरना न्याय की देवी की दोनों आंख पर पट्टी नहीं बंधी होती। इसका पता चला गया। हालांकि, कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन ट्रिपल तलाक को जारी रखने की पुरजोर वकालत भी कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुसलमान औरतों को जीवनदान दे ही दिया। इस फैसले के आने से पहले तक यह कहा जा रहा था कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह तय हो जायेगा कि मानवता जीतती है या मुस्लिम सांप्रदायिकता और अमानवीयता। एक बात समझ ली जाए कि अब मुस्लिम औरतें भी पढ़-लिख गई हैं और जाग उठी हैं। वे भी अब गुलामी की जंजीर को तोड़ने का मन बना चुकी हैं। अब इन्हें नामंजूर है कि इनके शौहर या परिवार के बाकी सदस्य इन्हें अपना गुलाम बानकर रखें। मध्य प्रदेश की उस बहादुर महिला के जच्चे को सलाम जिसने अपने विवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन सबकी शिकायत की जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। देश को इस तरह की महिलाओं के साथ खड़ा होना होगा। ■



आधी आबादी को पूरा अधिकार डबल इंजन की सरकार



मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

चतुर्थ चरण



- 1.50 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी
- 10 लाख स्वयं सहायता समूह : 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : 1.75 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, दीपावली व होली में निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर, ₹300 की सब्सिडी
- प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना : 55.20 लाख आवास
- पी.एम. स्वामित्व योजना : 66.59 लाख लाभार्थी महिलाओं को स्वामित्व प्रमाण पत्र
- पी.एम. स्वनिधि योजना : 2 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : 54.44 लाख महिलाएं लाभान्वित
- आंगनवाड़ी केंद्रों से वितरण : 1.77 करोड़ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड गेहूं, दलिया, चना, दाल एवं स्वाद्य तेल
- स्वच्छ भारत अभियान : 2.61 करोड़ शौचालय, महिलाओं के लिए अतिरिक्त 4,500 पिक शौचालय निर्मित
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना : 1.90 करोड़ बेटियां लाभान्वित
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : 3.10 लाख जोड़ों का विवाह
- हर घर नल योजना : 1.83 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पेय जल
- बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : 16.24 लाख बेटियां लाभान्वित
- बी.सी. सखी योजना : 58,000 ग्राम पंचायतों में नियुक्त
- रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम : 40 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण
- महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलाने में देश में अग्रणी
- पॉक्सो एक्ट : 7,320 अभियोगों में सजा
- सख्त अभियोजन: महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के 19,415 प्रकरणों में सजा
- 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना
- महिला हेल्पलाइन 1090 : 99.55% शिकायतों का निस्तारण
- मिशन शक्ति अभियान : तीन चरणों में महिला हेल्प डेस्क द्वारा 11,65,461 शिकायतों का निस्तारण
- महिला पी.ए.सी. बटालियन : बदायूं, लखनऊ व गोरखपुर में गठन
- सभी 1584 थानों में शक्ति मोबाइल एवं 10,417 महिला पुलिस बीट का गठन 20,740 महिला बीट पुलिसकर्मियों की नियुक्ति
- 18 परिक्षेत्र मुख्यालयों पर महिला साइबर सेल का गठन
- जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों/महिला थानों का गठन
- महिला श्रम शक्ति 6 वर्षों में हुई दोगुनी से अधिक वर्ष 2017-18 में 14.20% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में हुई 32.10%

हेल्पलाइन

1090

तुमने पॉवर लाइन

102

गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन

108

एम्बुलेंस सेवा

1098

चाइल्ड लाइन

181

तुमने हेल्पलाइन

112

पुलिस आपातकालीन सेवा

101

अग्निशमन सेवा

1930

साइबर हेल्पलाइन

1076

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश



सर्वसमावेशी विकास डबल इंजन की सरकार



भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अनेक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।



भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र

- भारतीय संविधान शिल्पी बाबासाहेब की स्मृति में लखनऊ में 1.34 एकड़ में बाबा साहेब की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना
- पुस्तकालय, शोध केंद्र, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह एवं संग्रहालय का निर्माण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाएं एवं उपलब्धियां

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :

- अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के एकीकृत विकास हेतु 10,384 ग्रामों का चयन। 3,800 ग्रामों के विकास के लिए 792 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित, शेष ग्रामों का वी.डी.पी. तैयार किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम :

- बेहतर सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए 2015 एवं 2018 में संशोधन कर अधिनियम को और सशक्त करते हुए 47 प्रकार के अत्याचारों का समावेश।
- अपराध एवं अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को 85,000 रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान। अब तक 1,27,305 प्रकरणों में 1,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

आम्बेडकर सामाजिक इन्वैशन इन्क्यूबेशन मिशन :

- उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :

- अनुसूचित जाति वर्ग के 11.37 लाख वृद्धजन को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :

- परिवार के कमाने वाले व्यक्ति के निधन पर आर्थिक सहायता का प्रावधान। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 6,99,259 परिवारों को 2,097 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :

- गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु प्रति जोड़ा 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 1,53,519 युगल लाभान्वित।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना : परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन -

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का संचालन एवं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी हेतु **गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी तथा हापड़** में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए **प्रयागराज** में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित।

छात्रवृत्ति योजना :

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान।

- पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 25.51 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को 651 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित।
- दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 67.19 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को 8,814 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय :

- निर्धन प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन। अनुसूचित जाति/जनजाति के 60 प्रतिशत छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था। इन विद्यालयों में 35,089 छात्र/छात्राओं पर 207 करोड़ रुपये व्यय।

छात्रावास :

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 261 छात्रावास संचालित। 63,603 छात्र-छात्राएं लाभान्वित।

क्यों लगा झटका धारा 370 की बहाली चाहने वालों को

ब्रजेश शर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाकर उन लोगों को अच्छा-खासा झटका दे दिया, जो चाहते थे कि राज्य में पहले वाली व्यवस्था की बहाली हो जाए और उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। किसी राज्य को खास कहना सरासर गलत और एक तरह से संविधान विरोधी है जो किसी राज्य को अलग अधिकार नहीं देता। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'एक देश-एक विधान और एक निशान' की विचारधारा को भी स्वीकृति मिल गयी और भारत के विघटन का सपना देखने वालों को करारा जवाब भी मिल गया। बेशक, धारा 370 को निरस्त करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही जाता है जिन्होंने अपनी हठ इच्छाशक्ति से सही मायनों में जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ा है। मैं भी उन सौभाग्यशाली सांसदों की श्रेणी में हूँ जिन्होंने 2019 में राज्य सभा में अमित भाई शाह के प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की फुल बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा। इस फैसले से सारा देश गदगद है। सिर्फ उन्हीं की छाती पर सांप लोट रहा है जो भारत की एकता और अखंडता को बना हुआ देखना नहीं चाहते। देश उनके इरादों को कभी सफल नहीं होने देगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, जो यह विरोध मात्र अपने काग्रेसी आकाओं को खुश करने के लिये कर रहे हैं। क्योंकि, उन्हें यह पता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट के अवमानना का सज़ान ले लिया तो वे बुरी तरह फसेंगे। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह पूर्णतः एक अस्थायी प्रावधान था।" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की



राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। अब यह मानकर चलिए कि जम्मू-कश्मीर का सर्वांगीण विकास और रफ्तार पकड़ लेगा। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर के 14 शिखर नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुके हैं, जिनमें तत्कालीन राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अफसोस होता है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के सवाल पर काग्रेस का रवैया बेहद नीचता भरा रहा है। काग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कहते रहे हैं कि केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो वे संविधान के अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल कर देंगे। हालाँकि, अब काग्रेस के नेता और जम्मू-कश्मीर के राजा रहे हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पर काग्रेस के शिखर नेताओं जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह बताना होगा कि वे दिग्विजय सिंह की राय के साथ हैं या नहीं? अर्थात् क्या काग्रेस चाहती है कि जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2020 से पहले की व्यवस्था लागू हो? काग्रेस के कई नेता चीख-चीखकर बेशर्मा से कहते रहे हैं कि धारा 370 को खत्म करना लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है। यकीन मानिए कि जिस भाषा में दिग्विजय सिंह मांग करते रहे हैं, वही तो पाकिस्तान भी बोलता है। चीन भी यही चाहता है। चीन

कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना अवैध और अमान्य है। वह भारत के आंतरिक मामले में दखल देने से बाज नहीं आता। चीन ने भारत के धारा 370 को हटाने के कदम को 'अस्वीकार्य' करार दिया था। अगर बात पाकिस्तान की करें तो उसका तो अब रहा-सहा चैन भी खत्म हो गया है। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो देर-सवेर मिल ही जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह का देश को भरोसा दिया है। पर अब अनुच्छेद 370 इतिहास के गटर में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य के नेता जैसा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला विरोध कर रहे हैं। उनसे यही उम्मीद भी थी। उन्हें बरगलाने वाली राजनीति के लिये कोई मसला रहा नहीं। पर उन्हें अब कौन पूछता है। आखिर अनुच्छेद 370 में क्या खास बात थी जिसकी मांग काग्रेस तथा कश्मीरी नेता करते रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि अनुच्छेद 370 राज्य को भारत से जोड़ने में विफल रहा था? अनुच्छेद 370 से ही कश्मीर में अलगाववाद बढ़ा था। क्यों वहाँ पर कभी अल्पसंख्यक आयोग नहीं बना? क्या वहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख नहीं रहते? अनुच्छेद 370 से राज्य के अल्पसंख्यकों के साथ घोर अन्याय हुआ। क्यों अनुच्छेद 370 के दौर में वहाँ पर सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वालों को आरक्षण नहीं मिला? ■

*With best
complement from*

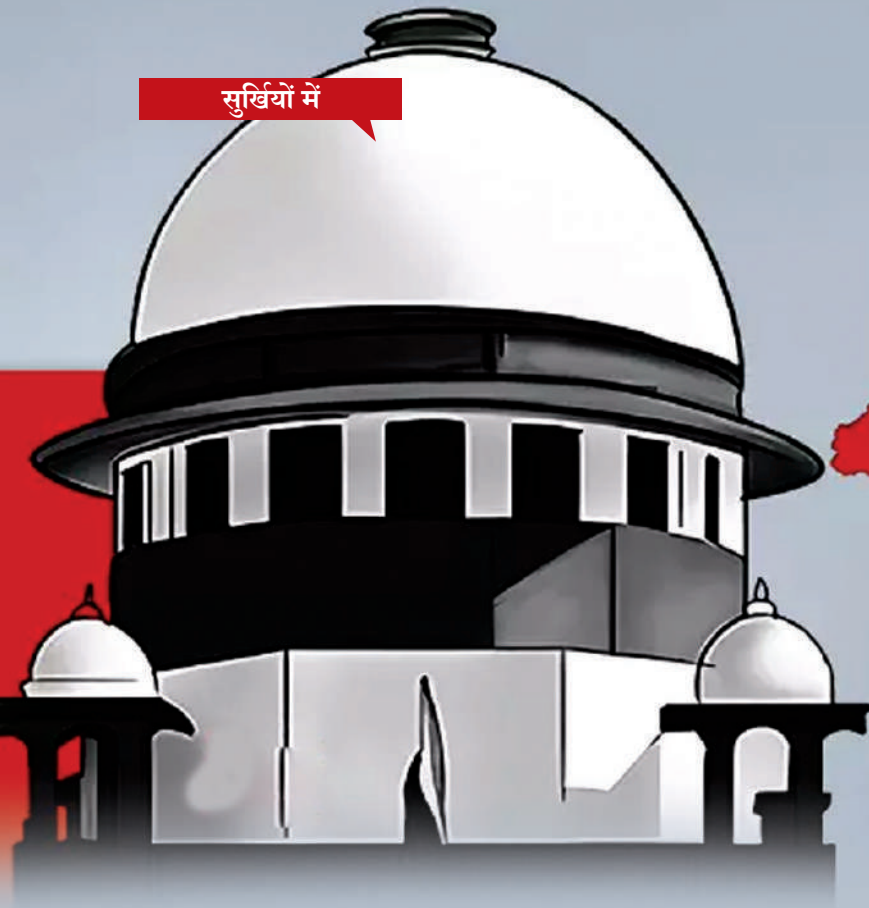
मै. श्री कृष्णा एसोसियेट्स

प्रोपराइटर: बासुदेव चौधरी

A Class Contractor, P.W.D.
Mathura

M: 9412777377, 7017469644

ARTICLE 370



जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने की बहस पर

पूर्ण विराम लगाना देशहित में है

उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लिखा कि अनुच्छेद-370 को निरस्त करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाईयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।

मृत्युंजय दीक्षित

भारत की संप्रभुता और जम्मू-कश्मीर प्रान्त के लिए 11 दिसंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन बनकर आया। इस दिन उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के निर्णय को वैध ठहराते हुए कहा कि यह एक अस्थायी धारा थी जिसे आज नहीं तो कल हटाना ही था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। अदालत ने कहा कि भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है और अनुच्छेद-370 को बेअसर करने से जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है और केंद्र सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक टिप्पणियां की हैं जिनमें कहा गया है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद जम्मू-कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लिए कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के शासन के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब संविधान सभा भंग कर दी गई तो सभा की केवल अस्थायी शक्ति समाप्त हो गई और राष्ट्रपति के आदेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था और राज्य के साथ किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का निरंतर प्रयोग दशांता है कि एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी और इस प्रकार से सीओ 273 अवैध है। जम्मू-कश्मीर का संविधान क्रियाशील है और इसे निरर्थक घोषित कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा और हम लद्दाख को अलग करने के फैसले को बरकरार रखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अंत में कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश करते हैं कि पुनर्गठन अधिनियम और राज्य के दर्जा 14 की धारा के अंतर्गत 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराये जायें।

न्यायालय ने एक यह व्यवस्था भी दी है कि राज्य में 1980 के बाद हुई सभी प्रकार की आतंकवादी/पलायन की घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनायी जाये जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय प्राप्ति का मार्ग खोलती है। इस व्यवस्था के आने के बाद 1980 के बाद घटी में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वारदातें हुई हैं उनकी जांच अब की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय की इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे तथा बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे।

जस्टिस कौल की ऐतिहासिक टिप्पणी

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 1980 से राज्य में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह आयोग आपराधिक जांच आयोग की तरह काम नहीं करेगा। जस्टिस कौल का मानना है कि आतंक के चलते राज्य की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने बहुत कुछ झेला है। इसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए जख्मों को ठीक करने की जरूरत है। राज्य एवं राज्य

राज्य में विकास का नया सूर्योदय

अनुच्छेद-370 के रद्द किये जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में विकास की राह खुली है पर अब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद वहां विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा है। वर्ष 2024 में कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू-कश्मीर में सड़कों, पुलों एवं सुरंगों के निर्माण से तस्वीर बदल रही है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल पहुंचने वाले एक करोड़ श्रद्धालुओं के लिए दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी है। जम्मू-कश्मीर राज्य भी तीव्र गति से डिजिटल हो रहा है और कई योजनाएं व सेवाएं ई-मोड पर उपलब्ध हो चुकी हैं। पर्यटन उद्योग को विकास के नये पंख लग रहे हैं जिसके अंतर्गत जनवरी-2022 से 31 दिसंबर 2022 तक राज्य में एक करोड़ 88 लाख 84 हजार 317 रिकार्ड पर्यटक आये। श्रीनगर की डल झील की रौनक वापस आ गयी है और फिल्मों की शूटिंग भी एक बार फिर प्रारंभ हो चुकी है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियां की अब चल पड़ी हैं जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या में भी कमी आ रही है। कुछ माह पूर्व हुई जी20 की बैठक के माध्यम से पूरे विश्व ने एक नया कश्मीर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह की संधी हुई और ठोस रणनीति के कारण अब राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद धीरे-धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। राज्य में पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। कश्मीर में 2010 में पत्थरबाजी से 112 लोगों की मौत हुई थी जबकि 2023 में पत्थरबाजी से एक भी मौत नहीं हुई। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अनुच्छेद-370 के कारण ही राज्य में अलगाववाद का जहर पनप रहा था वह मूल अब समाप्त हो चुका है किंतु राज्य की सुरक्षा के लिए वहां की जनसांख्यिकीय को भारत के पक्ष में करना ही होगा। अनुच्छेद-370 के समापन के बाद राज्य में विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा है जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलेगा।

से बाहर के तत्वों के द्वारा यहां के लोगों के विरुद्ध किये गये मानवाधिकारों के हनन की सामूहिक समझ विकसित करना ही मरहम लगाने की दिशा में पहला निष्पक्ष प्रयास होगा। आयोग के सहारे काफी हद तक उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाने से सम्बंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य के परिवारवादी नेता फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग व कई अन्य संगठन इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय पहुंच गये थे। उन सभी की याचिकाओं पर अगस्त से सितंबर माह के बीच 16 दिन चली सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय आया है जिस पर पर सभी देशवासियों और राजनैतिक दलों सहित अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान की भी दृष्टि थी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ वाली खंडपीठ के फैसले के बाद पाक परस्त अलगाववादी नेताओं व कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गयी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-370 व 35-ए को हटाने का निर्णय वैध बताये जाने के बाद जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निर्णय को अब संवैधानिक मान्यता मिल गयी है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित उस संपूर्ण विपक्ष की राजनीति को बहुत गहरा आघात लगा है जो राष्ट्रीय संप्रभुता के इस विषय को भी तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से देख रही थी। अनुच्छेद 370 पर विपक्षी नेता और अलगाववादी जो अनर्गल प्रश्न उठा रहे रहे थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर

उच्चतम न्यायालय ने दे दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब धारा 370 पर पूर्ण विराम लग चुका है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद अब जम्मू-कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह समान व्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उच्चतम फैसला आ जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के गुपकार गठबंधन के नेताओं व अलगाववादियों के होश उड़ गये हैं। जम्मू-कश्मीर में गुपकार गठबंधन के सभी नेता जिस प्रकार अदालत के निर्णय को मानने से इंकार करते हुए जिस प्रकार एक लंबे संघर्ष की बात कर रहे हैं वह एक चिंतनीय विषय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आ गयी है और वहां पर खलबली मची है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लिखा कि अनुच्छेद-370 को निरस्त करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाईयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है। जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है। ■

विधानसभा चुनावों की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 23 अप्रैल को एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा था कि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं। इसके बावजूद वह और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी।

डॉ. आशीष वशिष्ठ

इन दिनों सोशल मीडिया पर नोटों से भरी अलमारियों की कुछ तस्वीरों खूब वायरल हो रही हैं, जिनका संबंध कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू से है। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबरें सुर्खियों में रहीं। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर हुई। आयकर विभाग की इस छापेमारी में अब तक 351 करोड़ रुपए मिले हैं। साहू के ठिकानों में मिले बेहिसाब धनराशि ने फिर से एक बार देश में भ्रष्टाचार और कालेधन की लेकर बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लगातार तंज कस रही है। राजनीति से इतर ये प्रकरण एक गंभीर मामला है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जबरदस्त वार किया गया था। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और अधिक सख्ती से पेश आ रही है। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, जिनका देश सामना कर रहा है- भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब बीती 8 दिसंबर को किया गया एक्स पर उनका पोस्ट देखिए, जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान-ए-जंग कर 2024 से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया है। इस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव का एजेंडा और टोन को भी सेट कर दिया है।

याद कीजिए पीएम मोदी ने कहा था कि, न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी तकरीबन हर चुनावी रैली में पीएम भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से उठाते थे। कभी महादेव पेप घोटाला तो कभी खनन घोटाला, कभी लाल डायरी में दर्ज काले कारनामे तो कभी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक...। राजस्थान की ऐसी ही एक रैली में पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण की बातों को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के 3 बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इन तीनों की ही प्रतीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कांकर की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचारियों ने जो कुछ भी लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहता हूँ- छत्तीसगढ़ को लूटने वाले चाहे कोई भी हों, चाहे कितने भी ताकतवर हों, उन्हें सब कुछ लौटाना होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जून को पटना में विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक के बाद भी भोपाल में एक सभा में विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों पर जमकर चुटकियां ली थीं। पीएम मोदी ने कहा था कि आजकल बार-बार एक शब्द आता है- गारंटी। ये सारे विपक्षी दल भ्रष्टाचार की गारंटी हैं। ये गारंटी हैं लाखों-करोड़ रुपयों के घोटालों की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इनका एक फोटोशॉप कार्यक्रम हुआ। उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिल कर टोटल करेंगे तो ये सारे मिल कर कम से कम 20 लाख करोड़ रुपये के घोटाले की गारंटी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बगैर किसी ठोस कार्यक्रम के समाप्त हुई



विपक्षी दलों की बैठक पर प्रहार करते हुए कहा कि अकेले कांग्रेस का ही लाखों करोड़ों का घोटाला है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है और इसीलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है- घोटालों की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों में से किसी ने भी उस समय प्रधानमंत्री के आरोपों का खंडन तक नहीं किया। विपक्षी दल ईडी की कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मात खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के मामले में दखल देने से इंकार कर दिया था। बीती 28 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है और जब अदालत कोई फैसला सुनाती है, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है और उसे दीमक की तरह खोखला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीती 23 अप्रैल को एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा था कि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं। इसके बावजूद वह और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना लें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। केंद्र की तरफ से संसद में रखी गई जानकारी में भी ये बात सामने आई है। सरकार ने संसद को बताया है कि जुलाई 2014 से दिसम्बर 2020 तक यानी बीते छह साल में 340 बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार, अनियमितता या फिर

अक्षमता के चलते जबरन रिटायर किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को बल इस बात से मिलता है विपक्ष के कई नेता आज भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं और कई जमानत पर बाहर हैं। विपक्षी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामलों में अदालत ने कोई राहत नहीं दी है। विपक्ष के लिए बेशक भ्रष्टाचार मिटाने का मुद्दा प्रमुख न हो, पर इस मामले में भारत की स्थिति भयावह है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की 180 देशों की सूची में भारत को 40 अंकों के साथ 85वें पायदान पर रखा गया। निश्चित तौर पर राज्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही भारत की यह स्थिति बनी है। विशेषकर विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह विपक्षी दलों के लिए कभी भी चिंता का विषय नहीं बना। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को विपक्ष बदले की राजनीति करार देता है। लेकिन हालिया चुनाव नतीजों से उत्साहित केंद्र सरकार इन आरोपों से दबाव में आने वाली नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है। इस तरह उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने के संकेत दे दिए हैं। यह निश्चित है कि जब तक विपक्षी दल भ्रष्टाचार सहित राष्ट्रहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साफ नहीं करेंगे तब तक एकता होने के बावजूद देश के लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं है। भाजपा विपक्षी दलों को लगातार निशाने पर लेती रहेगी और इस बार लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे की गूंज जोर शोर से सुनाई देगी। ■

शिखर से शून्य की ओर जाता दिख रहा है बसपा का दलित मूवमेंट आंदोलन

मायावती के फैसले ने यूपी की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। क्योंकि उन्होंने बसपा के किसी नंबर दो के दमदार नेता की बजाय भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ज्यादा उचित समझा। यही परंपरा मान्यवर कांशीराम निभाते तो आज मायावती बसपा सुप्रीमो नहीं हो पातीं।

मनोज कुमार

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जैसे ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके तुरंत बाद मायावती पर भी वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगने लगा है। उनसे पूछा जा रहा है कि मान्यवर कांशीराम के साथ दलित मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बसपा नेताओं को बहन जी ने क्या इसी दिन के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था, ताकि उनके भतीजे के लिए राजनीति का रास्ता सुगम हो सके? हाल ही में मायावती ने अपने सांसद दानिश अली को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है, जो इस समय काफ़ी तेजी के साथ बसपा में अपनी पकड़ बना रहे थे। यह और बात है कि इतना सब होने के बाद भी मायावती ने सार्वजनिक मंच से उत्तराधिकारी घोषित करने की पार्टी की परंपरा को कायम रखा। करीब ढाई दशक पहले मान्यवर कांशीराम ने भी इसी तरह मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने भी लखनऊ में एक सभा में मंच से इसका ऐलान किया था। उस समय खासी राजनीतिक हलचल मची थी। कांशीराम के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन, कांशीराम ने मायावती की प्रतिभा का आकलन करने के बाद उन्हें यह पद देने का ऐलान किया था। इस घोषणा के करीब 6 साल बाद वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थीं, लेकिन मायावती के फैसले ने यूपी की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। क्योंकि उन्होंने बसपा के किसी नंबर दो के दमदार नेता की बजाय भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ज्यादा उचित समझा। यही परंपरा मान्यवर कांशीराम निभाते तो आज मायावती बसपा सुप्रीमो नहीं हो पातीं बल्कि उनकी जगह कांशीराम के परिवार का कोई सदस्य इस कुर्सी पर बैठा होता और हो सकता है वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होता। हालांकि, मायावती ने बसपा में उत्तराधिकारी घोषित करने की

जो पुरानी परंपरा पुरानी है, उसे जीवित जरूर रखा, लेकिन मायावती और मान्यवर कांशीराम के फैसले में जमीन आसमान का अंतर है। यदि ऐसा ना होता तो आज मायावती के भतीजे की जगह कोई और नेता मायावती की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी होता। अभी तक मायावती के भतीजे आकाश आनंद सियासत में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं, जिसके आधार पर उनकी राजनीतिक कुशलता का एहसास किसी को हुआ हो। गौरतलब है कि मायावती को मान्यवर कांशीराम जब राजनीति में लाए थे तो उसे समय वह आईएएस की तैयारी कर रही थीं। उसी दौरान दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में मायावती को बड़े नेताओं के बीच बोलने का मौका मिला। उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राज नारायण पर हमला बोला। राजनारायण दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। मायावती ने कहा कि आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। कांशीराम ने जब यह बात सुनी तो वह मायावती के घर पहुंच गए। कांशीराम ने आईएएस बनने की बजाय राजनीति में आने के लिए मायावती को प्रेरित किया। कांशीराम ने मायावती को समझाया कि अगर वह राजनीति में सफल हो जाती हैं तो दर्जनों आईएएस अधिकारी उनके नीचे काम करेंगे। मायावती दलितों के उत्थान के लिए चल रहे संघर्ष के दौर में कांशीराम के साथ जुड़ीं थीं। मायावती 1984 में बसपा का गठन होने के बाद उसमें शामिल हुईं और उसी साल पहला लोकसभा चुनाव कैराना से लड़ा। पहली बार 1989 में वह सांसद बनीं। इसके बाद वह चार बार यूपी की मुख्यमंत्री भी रहीं। मान्यवर कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लखनऊ में एक सभा में कांशीराम ने कहा कि मैं काफ़ी समय से यूपी कम आ पा रहा हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरी इस गैरहाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। यह कहकर उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह ऐसा वक्त था, जब पार्टी संघर्ष के दौर से

गुजर रही थी और 2002 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांशीराम के निर्णय से पार्टी के उन नेताओं को झटका लगा था, जिनको मायावती ने पार्टी से बाहर किया गया था। आरके चौधरी और बरखू राम वर्मा पार्टी में यह संदेश दे रहे थे कि मायावती के साथ उनके मतभेदों के बावजूद अब भी वे कांशीराम के पसंदीदा हैं। मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित करने की उस परंपरा को तो आगे बढ़ाया है, लेकिन एक बड़ा अंतर भी है। कांशीराम ने अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाकर एक मिसाल पेश की थी, जबकि मायावती ने अपने सगे भतीजे को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी जानकारों का कहना कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दलितों में लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर युवा चेहरे के तौर पर आते हैं। ऐसे में मायावती ने उनके मुकाबले सबसे युवा चेहरे 28 साल के आकाश को उत्तराधिकारी बनाया है। युवाओं में पकड़ बनाकर वह पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, उत्तराधिकारी बनने के बाद आकाश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मायावती जिस तरह कठिन परिस्थितियों से पार्टी को निकालकर लाई थीं, क्या वह ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? यह वह दौर है जब बड़े-बड़े दिग्गज देता प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत के सामने पानी भर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति उतार पर है। ऐसे में युवाओं को जोड़ने के साथ वरिष्ठों के साथ तालमेल बैठकर कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे? पार्टी ने उनको लगातार बड़ी जिम्मेदारियां दीं, लेकिन अब तक वह कुछ खास चमत्कार नहीं कर पाए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें देश भर में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। बेहतर नतीजों के जरिए उत्तराधिकार की जिम्मेदारी पर उन्हें खरा उतरना होगा। अगर वे संगठन पर पकड़ बनाने में मजबूत हुए तो उन्हें भी मायावती की तरह बड़ी सफलता मिल सकती है, मगर समस्या यह भी है कि मायावती इस समय अपनी सियासत के बहुत-बुरे दौर से गुजर रही हैं। उनकी दलित सियासत उतार पर है। ■

गूगल पर निर्भर होते जा रहे हैं छात्र, सामान्य ज्ञान की भी है कमी, क्या ऐसे ही हम बनेंगे

विश्व गुरु ?



उमेश चतुर्वेदी

उन छात्रों से जब सामान्य ज्ञान या समकालीन विषयों से कुछ सवाल पूछा तो उनका एक ही जवाब था, सर, गूगल तो है ना.. अंतर इतना था कि किसी की आवाज धीमी रही तो किसी को थोड़ी तेज। मुझे करीब आठ साल पहले का एक वाक्या याद आ गया। हाल ही में एक बड़े सरकारी मीडिया संस्थान में इंटरनेट पर रहे छात्रों से मुखातिब होने का मौका मिला। संस्थान ने योजना शुरू की है.. इंटरनेट पर लिए आए छात्रों को हर हफ्ते कुछ सत्र विषय विशेषज्ञों से मिलाना और उनका व्याख्यान कराना। इसी सिलसिले में मुझे भी बुलावा मिला। मेरी एक आदत है। मीडिया के छात्रों से मिलते ही उनकी पढ़ाई-लिखाई के साथ ही उनके पसंदीदा अखबार-पत्रिका, टीवी कार्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त करना मेरी आदत में शुमार है। लगे हाथों कुछ सामान्य ज्ञान और समकालीन विषयों से जुड़ी जानकारियों को लेकर पूछताछ भी कर लेता हूँ। सो, इस बार भी वैसा ही किया। मीडिया के छात्रों के जवाब आश्चर्यजनक रहे। किसी की आदत में अखबार पढ़ना शामिल नहीं था। ना अंग्रेजी का, ना ही हिंदी का। यहां यह जान लेना होगा कि इंटरनेट पर रहे छात्रों में तकरीबन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था। इलाहाबाद, मोतिहारी, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल,

चंडीगढ़ जैसी जगहों के एक-एक या दो-दो छात्र थे। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की छात्रा भी इंटरनेट के उस समूह में शामिल थी। बेंगलुरु वाले छात्र तो वहां के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से थे, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। किसी को नियमित रूप से अपने इलाके के अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी। किसी खबरिया चैनल का कोई प्रोग्राम भी उनका पसंदीदा नहीं था। अलबत्ता सभी मीडिया के ही छात्र थे। उन छात्रों से जब सामान्य ज्ञान या समकालीन विषयों से कुछ सवाल पूछा तो उनका एक ही जवाब था, सर, गूगल तो है ना.. अंतर इतना था कि किसी की आवाज धीमी रही तो किसी को थोड़ी तेज। मुझे करीब आठ साल पहले का एक वाक्या याद आ गया। तब मैं एक टीवी चैनल का कार्यक्रम का पत्रकार था। शुरूआती स्तर के लिए पत्रकारों की जरूरत थी। इसलिए उन दिनों दिल्ली के कुछ छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार के दौरान एक लड़की से जब सामान्य जानकारी से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए तो उनका वह जवाब तक नहीं दे पाई। वह भी दिल्ली के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। जब उसके कॉलेज की प्रतिष्ठा की याद दिलाई गई तो उसने तपाक से जवाब दिया था, सर गूगल है न.. जरूरत पड़ी तो उससे किसी भी सवाल

का जवाब पूछ सकते हैं। पत्रकारिता के प्रोफेशन में आने वाले लोगों से उम्मीद की जाती है कि उनका सामान्य ज्ञान, उनकी भाषा और उनकी सोच औरों से बेहतर होगी। बेशक वे किसी एक विषय के अगाध विद्वान ना हों, लेकिन कम से बुनियादी स्तर का उनके पास बाकियों की तुलना में ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा अखबार वे नियमित रूप से पढ़ेंगे। टेलीविजन के किसी विशेष चैनल आदि के समाचार आधारित कार्यक्रम जरूर देखेंगे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। वैसे तो टेलीविजन चैनल देखकर आप अपना सामान्य ज्ञान उस स्तर तक अपडेट नहीं कर सकते, जैसे अखबार पढ़कर या किसी वेबसाइट को पढ़कर। टेलीविजन चैनल तो चमत्कार, कुकुरझोंझ और हंगामे के प्रतीक बन चुके हैं। तमाशा कल्चर उनका प्रमुख तत्व है। रही बात आज के दिग्गज यू ट्यूबर्स की, तो वे पत्रकार कम, पक्षकार ज्यादा हैं। उनकी अपनी पसंद और ना पसंद उनके यू ट्यूब चैनल पर हावी रहती है। आज कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे पत्रकारिता की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इस स्थिति को लाने में क्या पत्रकारिता का योगदान नहीं है? निश्चित तौर पर इसका भी योगदान है और इसके सबसे बड़ी वाहक बनी है पत्रकारिता की शिक्षा और समाचार चैनलों की सौंदर्यशास्त्रीयता से युक्त कुकुरझोंझ। तकनीक और संचार के विकास ने पत्रकारिता की दुनिया को आसान बनाया है। लेकिन यह आसानी बढ़ते-बढ़ते मेधा को पंगु करने तक पहुंच गई है। एक तरह से अब इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है। यह निर्भरता अब कक्षाओं में भी दिखने लगी है। जिन कक्षाओं में फोन रखना संभव है, उन कक्षाओं में अध्यापक या प्रोफेसर का व्याख्यान शुरू हुआ नहीं कि छात्र गूगल कर खोल बैठ जाते हैं और प्रोफेसर के ज्ञान को सर्च इंजन में डाल जांचने लगते हैं। पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाने के अवसर मुझे अक्सर मिलते रहते हैं। लेकिन मैं छात्रों से उस वक्त कड़ाई से पेश आता हूँ। सबका फोन बंद करा देता हूँ, इस सुझाव के साथ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को नोट करें और उसकी सत्यता की जांच बाद में करें। कक्षा में व्याख्यान के साथ गूगल को चलाने से छात्र कक्षा में अपना ध्यान नहीं लगा पाता और अध्यापक का भी ध्यान भंग होता है। तकनीक का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ है। संचार क्रांति भी पूरी दुनिया में आई है। लेकिन जिन्हें अब विकसित देश मानते हैं, जो समृद्धि में हमसे कोसों आगे हैं, जिन्होंने ज्ञान आधारित समाज बनाया है, वहां कक्षाओं में फोन और गूगल पर बंदिष है। लेकिन हमारी व्यवस्था ठहरी अति लोकतांत्रिक, अगर ऐसी बंदिषें यहां लगाई जाएं तो सोशल मीडिया के दौर में हंगामा हो सकता है, सवाल उठ सकता है। ■

क्यों इतनी घुमक्कड़ी करने लगे हिन्दुस्तानी



आप देश के किसी भी हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आपको वहां पर एक जैसा नजारा ही देखने में आएगा। उधर आने जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ नजर आएगी। लगता है कि सारा देश ही घूमने के मूड में है। जैसे ही दफ्तरों में दो-तीन दिन के एक साथ अवकाश आते हैं तो लोग उन छुट्टियों में कुछ और छुट्टियों को जोड़कर किसी पर्यटक स्थल के लिए निकल जाते हैं। उन्हें समद्री तट से लेकर पहाड़ और अभयारण्यों से लेकर धार्मिक स्थल तक सबकुछ ही पसंद आ रहे हैं। एक बात और कि भारतीय सिर्फ देश के अंदर ही घूमकर संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें देश से बाहर जाना भी अच्छा खासा रास आ रहा है।

विकास शर्मा

एक निष्कर्ष के अनुसार, पिछले साल यानी 2022 में करीब दो करोड़ हिन्दुस्तानी देश से बाहर घुमक्कड़ी के लिए निकले। यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। भारतीय लंदन, पेरिस, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और दूसरे शहरों के अलावा केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, सिडनी मेलबोर्न, पर्थ, हॉगकांग वगैरह जा रहे हैं। दुबई और सिंगापुर के बाजारों में घूमते हुए तो लगता है कि आप किसी भारतीय शहर में ही हैं। वहां पर हजारों भारतीय रोज पहुंच रहे हैं। दरअसल आर्थिक उदारीकरण के बाद हिन्दुस्तानियों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने भी मन ही मन दुनिया को देखने का फैसला भी कर लिया। अब हिन्दुस्तानी कमाए हुए पैसे को गांठ में बांधने भर के लिए राजी नहीं है। उन्हें तो घूमना है। याद नहीं आता कि अब से पहले कब हिन्दुस्तानी आजकल की तरह

से घूमने के लिए घर से निकले थे। बेशक, दुनिया को जानने के लिए यायावरी जरूरी है। आप अगर घूमेंगे ही नहीं तो दुनिया को जानेंगे-समझेंगे कैसे। घुमक्कड़ी की चर्चा होगी तो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम तुरंत जेहन में आएगा। वे सदैव घुमक्कड़ ही रहे। उनकी सन् 1923 से विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसका अंत उनके जीवन के साथ ही हुआ। ज्ञानार्जन के उद्देश्य से प्रेरित उनकी यात्राओं में श्रीलंका, तिब्बत, जापान और रूस की यात्राएँ विशेष रही थीं। वे चार बार तिब्बत पहुंचे। वहां लम्बे समय तक रहे और भारत की उस विरासत को जाना, जो हमारे लिए अज्ञात और विस्मृत हो चुकी थी। वे 1907 में घर से भागकर चार मास तक कोलकाता में रहे। वे काशी में भी रहे। उन्होंने वहां रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। वे पैदल ही अयोध्या होते हुए मुरादाबाद पहुंचे और वहाँ से हरिद्वार गए। हरिद्वार से हिमालय, देवप्रयाग, टिहरी,

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की। फिर प्रयाग की प्रदर्शनी देखने के लिए घर से निकल गए। गांधी जी भी बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। वे रेलों से खूब सफर किया करते थे। घुमक्कड़ी के चलते उन्होंने देश के चप्पे-चप्पे को देखा और भारत को जाना। गुरु नानक देव जी ने 24 साल में दो उपमहाद्वीपों के 60 प्रमुख शहरों की पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 28 हजार किमी का सफर किया। उनकी यात्राओं का मकसद समाज में मौजूद ऊंच-नीच, जात-पात, अंधविश्वास आदि को खत्म कर आपसी सद्भाव, समानता कायम करना था। वे जहां भी गए, एक परमात्मा की बात की और सभी को उसी की संतान बताया। बाबा नानक अपनी पहली यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, चटगांव से होते हुए बर्मा (म्यांमार) पहुंचे वहां से वे ओडिशा, छत्तीसगढ़,





आखिर हम बौद्ध की भूमि होने के बावजूद दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित करने में क्यों असफल रहे। कुछ साल पहले तक राजधानी के दिल कनॉट प्लेस में बड़ी तादाद में विदेशी घूम रहे होते थे। अब यह वहां बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। कनॉट प्लेस के एक प्रमुख शो-रूम के स्वामी ने बताया कि कनॉट प्लेस में घूमने वाले भिखारी विदेशी पर्यटकों को बहुत परेशान करते हैं। इसलिए उन्होंने यहां आना ही बंद कर दिया है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत को अपने यहां विदेशी पर्यटकों की आवक को बढ़ाना है तो उसे पर्यटकों के हितों का ध्यान देना होगा।

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हरियाणा होते हुए वापस आए थे। तो भारत में प्राचीनकाल से ही यायावरी करने वाले रहे हैं।

यूं तो सारा भारत अब घुमक्कड़ हो चुका है, पर इस मोर्चे पर गुजराती और बंगाली बाकी से अब भी कुछ आगे ही हैं। आपको देश और देश से बाहर गुजराती पर्यटक मिलेंगे। गुजराती दुनियाभर में बसे भी हुए हैं। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक में। मुझे याद है कि एक बार मैं मिस्र की राजधानी काहिरा में पिरामिडों को निहार रहा था। वहां पर बहुत सारे गुजराती भी आ रहे थे बसों में। उनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। मैंने एक महिला से पूछा- क्या आप भारत के गुजरात प्रांत से हैं? उस महिला का उत्तर था- हम गुजराती हैं पर केन्या के। फिर उसने मुस्कराते हुए कहा कि हम लोग केन्या में दशकों पहले बस गए थे। हालांकि हमारी भाषा और संस्कार पूरी तरह से गुजरात की धरती के हैं। आप

बंग भाषियों को भी दूर-सुदूर की खाक छानते हुए देखेंगे। खुशवंत सिंह कहते थे कि आप ज्ञान अर्जित दो तरह से कर सकते हैं- पहला, पढ़कर और दूसरा, घूमकर। यह बात पूरी तरह से सही है। आप जब किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो आपको वहां के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का भी मौका मिलता है। घुमक्कड़ी किसी भी इंसान को समृद्ध बनाती है। मैं हाल के दौर में इस तरह के बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया हूं, जो समय-समय पर देश के अलग-अलग भागों जाते हैं। कभी-कभी देश से बाहर निकल जाते हैं। उनसे बात करके लगता है कि घुमक्कड़ी उन्हें बेहतर इंसान बना रही है। घुमक्कड़ी का मतलब सिर्फ खानपान ही नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस लिए भी सफर पर निकल जाते हैं ताकि उन्हें भांति-भांति के डिशेज के साथ न्याय करने का मौका मिल जाता है। घुमक्कड़ी का लक्ष्य सिर्फ पेट पूजा नहीं होना

चाहिए। आपको नई-नई जगहों के समाज और संस्कृति को भी समझना होगा। अगर भारत से लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर से भारत में पर्यटक आ भी रहे हैं। जानकारों के अनुसार, कोरोना के असर से ठीक एक साल पहले साल 2019 में भारत में लगभग 1.93 करोड़ विदेशी पर्यटक आए। उसके बाद से भारत में विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला 75 फीसद तक गिरा। चूंकि अब हालत सामान्य हो चुके हैं, इसलिए भारत में विदेशी पर्यटकों की आवक को बढ़ाना होगा। भारत में ताजमहल, गुलाबी नगरी जयपुर, पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग, असीमित जल का क्षेत्र कन्याकुमारी, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर समेत अनगिनत अहम पर्यटन स्थल हैं। हमारे यहां भगवान बुद्ध से जुड़े अनेक अति महत्वपूर्ण स्थल हैं। भारत में बौद्ध के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों के साथ एक समृद्ध प्राचीन बौद्ध विरासत है। ■



रेडियोलॉजिस्ट

के क्षेत्र में हैं करियर की अपार संभावनाएं

मेडिकल फील्ड में जाने के इच्छुक छात्र रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मेडिकल की फील्ड में यह एक आकर्षक कोर्स है। इस फील्ड में भविष्य में काफी ज्यादा ग्रोथ है। 12वीं करने के बाद आप यूजी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

विनय शर्मा

मेडिकल फील्ड में जाने के इच्छुक छात्र रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मेडिकल की फील्ड में यह एक आकर्षक कोर्स है। इसमें रेडियोग्राफर एक्सरे की मदद से मरीज की रेडियोग्राफी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे मरीज की बीमारी का सटीक पता लगाया जाता है। बता दें कि एक रेडियोग्राफर रेडियोग्राफी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक्स-रे के अलावा सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की भी स्टडी करता है। ऐसे में अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस फील्ड के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

रेडियोलॉजी का क्षेत्र

आपको बता दें कि रेडियोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और दूसरे का नाम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में एक्सरे और अन्य इमेजिंग तकनीक की सहायता से बीमारी और चोट का पता लगाया जाता है। तो वहीं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हेल्थ एक्सपर्ट इमेजिंग की व्याख्या कर कुछ हद तक सर्जिकल प्रोसीजर के काम को भी करता है।

संभावना

रेडियोलॉजी टेक्नॉलॉजिस्ट का कोर्स कर आप अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं। इस फील्ड में भविष्य में काफी ग्रोथ है। अस्पतालों, क्लिनिकों और फिजिशियनों के ऑफिस में ट्रेड व पेशेवर रेडियोलॉजी की मांग बढ़ती जा रही है। इस फील्ड में संबंधित कोर्स पूरा करने के बाद आप रेडियोलॉजी टेक्निशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्निशियन/डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नॉलॉजिस्ट/रेडियोग्राफर, एमआरआई टेक्निशियन, सीटी टेक/सीएटी स्कैन टेक्नॉलॉजिस्ट/सीटी स्कैन टेक्नॉलॉजिस्ट बन सकते हैं।

कोर्स

इस फील्ड में बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स का आप्शन मौजूद है। 12वीं करने के बाद आप यूजी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

सर्टिफिकेट कोर्स

- सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी डायग्नोस्टिक
- सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी असिस्टेंट
- सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी
- डिप्लोमा कोर्सेज
- डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरापी
- डिप्लोमा इन रेडियो-डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी
- यह कोर्स 2 साल का होता है।
- बैचलर कोर्स
- रेडियोग्राफी में बीएससी
- मेडिकल रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी में बीएससी (ऑनर्स)
- मास्टर कोर्स
- एक्स-रे रेडियोग्राफी और अल्ट्रा सोनोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
- रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
- रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा



जानिए कैसे बनें रेडियोलॉजिस्ट

बैचलर डिग्री पूरी करने के साथ रेडियोलॉजिस्ट का करियर शुरू होता है। मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद आपको एमओ या डीओ में डिग्री दी जाती है। इसके बाद आप मेडिकल लाइसेंस के रूप में भी आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आप बतौर फिजिशियन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए फिजिशियन को चार साल का रेडियोलॉजी रेजिडेंसी कोर्स पूरा करना पड़ता है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए स्टेट लाइसेंस भी काफी अहम होता है। इसमें आपको दो भाग में परीक्षा देनी होती है, उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। इस कोर्स में दो एग्जाम में शरीर की रचना, मेडिसिन, इमेजिंग से संबंधित तकनीक और फिजिक्स आदि को कवर किया जाता है।

ये हैं जॉब प्रोफाइल

- अल्ट्रासाउंड टेक्निशियन/डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर
- सीटी टेक/ सीएटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट/सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट
- अल्ट्रासाउंड टेक्निशियन/डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर

- रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट/रेडियोग्राफर
- एमआरआई टेक्निशियन
- रेडियोलॉजी टेक्निशियन
- रेडियोलॉजी असिस्टेंट
- रेडियोलॉजी नर्स

रेडियोलॉजिस्ट

इस फील्ड में आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप कई विभिन्न प्रोफाइल पर काम कर अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप बतौर रेडियोलॉजिस्ट प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पब्लिक हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक लैब में काम कर सकते हैं।

सैलरी

आपको बता दें कि जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हर रेडियोलॉजिस्ट को सैलरी मिलती है। वहीं अनुभव के साथ सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो बतौर रेडियोलॉजिस्ट आप 70 हजार डॉलर तक भी सैलरी उठा सकते हैं। वहीं भारत में रेडियोलॉजिस्ट को 5 लाख से भी ज्यादा का सालाना पैकेज मिलता है। ■

कहां गए वे पुरतैनी फैमिली डॉक्टर

हरिश्चन्द्र शर्मा

अगर आपकी उम्र 45-50 साल से अधिक होगी तो आपको याद होगा कि पहले हर शहर की हर कॉलोनी में वे डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, जिन पर सैकड़ों परिवार भरोसा रखते थे। वे परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर उसके पास तुरंत चले जाते थे। वे डॉक्टर रोगी का कायदे से इलाज करते थे क्योंकि, वे रोगी को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे। वह रोगी की सारी व्यथा को सुनने के बाद सही दवाई बताता था। क्योंकि उसे रोगी के परिवार के हरेक सदस्य के बारे में विस्तार से जानकारी हुआ करती थी। बहुत अवसरों पर तो इनमें पारिवारिक संबंध भी हुआ करते थे। उसे ही कहा जाता था फैमिली डॉक्टर। अब फैमिली डॉक्टरों की संस्था लुप्त सी हो गई है। उनकी जगह ले ली है क्लिनिकों, नर्सिंग होम और बड़े अस्पतालों में बैठने वाले डॉक्टरों ने। उनका अपने किसी भी रोगी से कोई संबंध नहीं होता। वह फैमिली डॉक्टर से बिल्कुल ही अलग होता है। फैमिली डॉक्टर को जब भी बुलाया जाता था तो वह अपना डॉक्टर का बैग लेकर मरीज के पास पहुंच जाता था। रोगी को देखने के बाद रोगी के घर में चाय-नाश्ता करने के बाद ही जाता। लेकिन, अब वह परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिहार के बेगूसराय में डॉ. अमृता सैकड़ों परिवारों की फैमिली डॉक्टर हुआ करती थीं। बीती दीवाली से पहले उनके निधन से उनके अनगिनत रोगी शोक में डूब गए। जानी-मानी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता डेगू संक्रमण का शिकार हो गयीं। प्रतिभाशालिनी डॉक्टर थीं अमृता मैडम सहृदय और संवेदनशील चिकित्सक थीं। हरेक रोगी का पूरे मन से इलाज करती। डॉ. अमृता गरीब और दूरदराज से आये रोगियों को भी अपना समझकर इलाज करती थीं। उनके रोगी आज के दिन अपने को अनाथ महसूस कर रहे हैं। उनके लिए सात्वना के कोई शब्द नहीं मिलते। नियति की क्रूरता का कोई उत्तर नहीं मिलता। वह सच में एक समर्पित फैमिली डॉक्टर थीं। श्रमिकों के शहर कानपुर के रहने वाले मित्र बताते हैं कि वहां पर कुछ साल पहले तक हर मोहल्ले में दो-तीन फैमिली डॉक्टर सक्रिय रहते थे। वे तेज बुखार, जोड़ों में भयंकर पीड़ा और शरीर के बाकी भागों में किसी तकलीफ की स्थिति में रोगियों का इलाज कर दिया करते थे। वे दवाएं लिखते और रोगी उन्हें लेने के बाद ठीक होने लगता। इतना बोल देते कि अगर दवा काम नहीं करेगी तो तभी जांच करावेंगे। पर आमतौर पर फैमिली डॉक्टर को दवा लेने के बाद मरीज का बुखार उतर जाता, उल्टियां नहीं होती और बदन दर्द में भी आराम मिल जाता। राजधानी के करोल बाग में भी



कुछ साल पहले तक डॉ. कुसुम जौली भल्ला नाम की एक मशहूर फैमिली डॉक्टर थीं। वह जनरल फिजिशियन के साथ-साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। उनके पास वेस्ट दिल्ली के बहुत सारे लोग आते। डॉ. कुसुम अपने रोगियों से पारिवारिक संबंध बना लेतीं। वह कथाकार भीष्म साहनी से लेकर न जाने कितने परिवारों की फैमिली डॉक्टर भी थीं। डॉ. कुसुम के रोगी उन्हें सुबह पार्क में ही घेर लेते थे। वहां पर रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद चालू हो जाता और दवाई बता दी जाती। ये सिलसिला लगातार जारी ही रहता था। उनके क्लिनिक में 'तमस' जैसी कालजयी रचना के लेखक भीष्म साहनी भी आते थे। भीष्म साहनी की मृत्यु के बाद डॉ. कुसुम बेमन से ही कभी-कभार पार्क जातीं। अब उनका वक्त अपने मेडिकल सेंटर में ही बीतता। सुबह से शाम तक रोगी आते-जाते रहते। उनमें महिलाएं ही अधिक होतीं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद डॉ. कुसुम ने 'अपना होप' नाम से क्लिनिक खोला था। उनका बांझ स्त्रियों के इलाज में महत्वपूर्ण शोध था। डॉ. कुसुम देश की उन पहली चिकित्सकों में थीं, जिन्होंने सैकड़ों निःसंतान दम्पतियों को कृत्रिम गर्भाधान विधि से संतान सुख दिया था। वह महिला बांझपन के लक्षण, कारण, इलाज, दवा, उपचार पर निरंतर अपने रिसर्च पेपर देश-विदेश में होने वाले सम्मेलनों में प्रस्तुत कर ही रही थीं। पर डॉ. कुसुम की 2013 में अकाल मृत्यु से बहुत रोए थे उनके रोगी भी। अब तो रोगी डॉक्टरों के पास जाने से भयभीत रहते हैं। उन्हें पता होता है कि डॉक्टर साहब उन्हें एक बाद एक टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे। यह अच्छी बात है कि कुछ डॉक्टरों ने रोगियों के अनाप-शनाप टेस्ट करवाने की बढ़ती मानसिकता पर विरोध भी जताया है। वे इन

टेस्ट को बंद करने की जोरदार तरीके से वकालत कर रहे हैं। किसी डॉक्टर को कायदे से रोगी को कितने टेस्ट करवाने के लिए कहना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो डॉक्टर ही दे सकते हैं, पर रोगियों को अनेक टेस्ट करवाने के लिए कहना अब रोगियों और उनके संबंधियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। उस दीन-हीन रोगी को पता ही नहीं होता कि जिन टेस्ट को करवाने के लिए उससे कहा जा रहा है, उसकी उसके इलाज में कितनी उपयोगिता है। चूंकि डॉक्टर साहब का आदेश है तो उसका पालन करना उस बेचारे रोगी का धर्म है। यह सब डॉ. कुसुम और डॉ. अमृता जैसे डॉक्टर नहीं करते थे। इसलिए ही इन डॉक्टरों का समाज में सम्मान था। उन्हें भगवान समझा जाता था। अब तो शायद ही कोई बहुत भाग्यशाली रोगी होगा, जिसे डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहा हो। कुछ डॉक्टरों की इसी सोच को चुनौती दे रहे हैं जिनमें हैं, राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. राजीव सूद, एम्स के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बलराम भागव और सर गंगाराम अस्पताल के गेस्ट्रो विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. समीर नंदी। डॉ. राजीव सूद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तथा एम्स के छात्र रहे। एम्स से यूरोलोजी की डिग्री लेने के बाद वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़े। डॉ. राजीव सूद 40 सालों की सरकारी सेवा करने के बाद हाल ही में रिटायर हुए तो उनके सैकड़ों रोगी परेशान हैं। वे तो निस्वार्थ भाव से रोगियों का इलाज कर रहे थे। मुश्किल से मिलते हैं उनके जैसे डॉक्टर। उन्होंने बाबू जगजीवन राम से लेकर न जाने कितने रोगियों का इलाज किया। उन्होंने ही फ्राइड सम्राट नटवरलाल का भी इलाज किया था। ■

सर्दियों में बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हैं

ये ड्राई फ्रूट्स

डॉ. हेमा भगौर

मौसम में बदलाव आने के साथ बड़ों से लेकर बच्चों तक को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मौसम में बदलाव आने के साथ ही हमें कई तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। सर्दियों के मौसम में लोगों को सर्दी-जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। जिसके कारण वह जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दी के मौसम में किस तरह से आप बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जानें कि बच्चों को की सेहत के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स फायदेमंद होते हैं।

बादाम

बादाम बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी यह लाभकारी होता है। बादाम में विटामिन ए, विटामिन बी2, प्रोटीन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वहीं ठंड के मौसम में बादाम के सेवन से खांसी और कफ में फायदा मिलता है। वहीं इसमें कई प्रकार के

एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है।

छुहारे

सर्दी के मौसम में वायरस से बचाने के लिए बच्चों को छुहारे खाने के लिए देना चाहिए। छुहारे में मिनरल्स और विटामिन की प्रचुर मात्रा पायी जाती है। जो बच्चों के शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना बच्चे को छुहारा खाने के लिए देते हैं। तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है।

अखरोट

अखरोट में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दी में बच्चों को अखरोट खिलाने से इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और वह जल्दी बीमार नहीं होते हैं। बता दें कि अखरोट में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर का कैंसर से बचाव करते हैं और त्वचा को नमी देने का काम करते हैं।

सर्दियों के मौसम में लोगों को सर्दी-जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दी के मौसम में किस तरह से आप बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं।

काजू

सर्दियों में काजू का सेवन कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वहीं काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बच्चों के चेहर पर निखार लाने में सहायक होता है। काजू स्वाद में भी अच्छा होता है, जिसके कारण बच्चे इसे चाव से खाते हैं।

खजूर

सर्दी के मौसम में न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों की सेहत के लिए खजूर काफी फायदेमंद होता है। खजूर में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स और अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है।

बच्चों को ऐसे खिलाएं ड्राई फ्रूट्स

अगर आप सोच रही हैं कि बच्चों को किस तरह से ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, तो आप बादाम शेक बनाकर उन्हें दे सकती हैं। इसके लिए बादाम और किशमिश रातभर के लिए भिगो दें। फिर सुबह इन्हें बच्चों को खिलाएं। इसके साथ ही आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी बनाकर भी दे सकती हैं। ■



सेहत ही नहीं त्वचा के लिए भी फायदेमंद हैं ये फल और सब्जियां, मिलेगा नेचुरल ग्लो



नीतू शर्मा

कई ऐसे फल और सब्जियां होती हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आज हम आपको इन फलों और सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके सेवन से आपको सेहत संबंधी लाभ मिलने के साथ ही स्किन संबंधी फायदे भी मिलते हैं। फलों और सब्जियों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। फलों और सब्जियों में मौजूद फाइबर न सिर्फ पाचन को स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा के लिए भी लाभकारी होती है। कई ऐसे फल और सब्जियां होती हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन फलों और सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके सेवन से आपको सेहत संबंधी लाभ मिलने के साथ ही स्किन संबंधी फायदे भी मिलते हैं।

शकरकंद

आपको बता दें कि सेहत के साथ-साथ शकरकंद स्किन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। शकरकंद में बीटा केरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी त्वचा को नेचुरल रूप से हेल्दी रखने में मददगार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की

मात्रा भी पायी जाती है। जो त्वचा संबंधी इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। शकरकंद को उबालकर खाने से त्वचा को फायदा मिलता है।

एवोकाडो

स्किन के लिए एवोकाडो का सेवन भी लाभकारी माना जाता है। एवोकाडो में विटामिनस, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से आपकी त्वचा अंदर से साफ होता है। जब स्किन अंदर से साफ होती है तो बाहर भी इसका निखार साफ पता चलता है। आप चाट या फिर शेक के तौर पर भी एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं।

खीरा

खीरा में पानी की पर्याप्त मात्रा पायी जाती है। इसके सेवन से त्वचा हाइड्रेड रहती हैं। वहीं खीरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। खीरे के नियमित सेवन से स्किन हाइड्रेट रहने के साथ ही माइस्चराइज रहती है।

संतरा

विटामिन सी से भरपूर संतरा त्वचा की सेहत के

लिए काफी अच्छा माना जाता है। संतरा में आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी और ग्लोइंग रखता है। साथ ही संतरे के सेवन झुर्रियां कम होने के साथ कोलेजन बढ़ता है।

पपीता

हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में पपीता भी अहम भूमिका निभाता है। पपीता में मिनरल्स के साथ-साथ विटामिन-ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। जो स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ ही यह त्वचा को हाइड्रेट भी रखता है। ऐसे में आप रोजाना पपीते का सेवन कर सकते हैं।

अनानास

स्किन को हेल्दी रखने में अनानास भी मददगार होता है। अनानास में विटामिन ए, सी की अधिक मात्रा पायी जाती है। इसमें मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। वहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। जो चोट को जल्दी रिकवर करते हैं। इसके सेवन से आपकी त्वचा हील होने के साथ ही ग्लोइंग भी बनती है। ■

सम्मेलनाय नमः



डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

वास्तव में सम्मेलन उन लोगों का समूह होता है जो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समूह बनने पर तीसमार खाँ बनने का दावा ठोकते हैं। यहाँ कुछ हासिल करने से ज्यादा समय-पैसे खर्च करने के बढ़िया बहाने खोजे जाते हैं। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब समूह में फोड़ने की सोचते हैं तो उसी समूह को सम्मेलन का नाम दे दिया जाता है। जी हाँ सम्मेलन! भीड़ में साँप नहीं मरता और सम्मेलन में समस्या का समाधान नहीं होता। साँप मर जाए तो लाठियों का और समाधान हो जाए इन सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक ढंसने के लिए और दूसरा समय-पैसे की खपत के लिए होना जरूरी है। इसीलिए दुनिया में इतनी लाठियों और बुद्धिजीवियों के होने के बावजूद दोनों का अस्तित्व जस का तस और अक्षुण्ण है। वास्तव में सम्मेलन उन लोगों का समूह होता है जो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समूह बनने पर तीसमार खाँ बनने का दावा ठोकते हैं। यहाँ कुछ हासिल करने से

ज्यादा समय-पैसे खर्च करने के बढ़िया बहाने खोजे जाते हैं। इनके निरंतर चलने से बिस्कुट जैसे नरम और चाय जैसे गरम लोगों का मेल-मिलाप होता है, जो कि ऐसे संदर्भों में एक-दूसरे के पूरक का काम करते हैं। देखा जाए तो हमारे सम्मेलनों में पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता है। यहाँ प्रतिभागों से अधिक संविधान का और संविधान से अधिक उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वालों का आदर-सत्कार किया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सम्मेलनों की पूंछ हनुमान जी की पूंछ से भी लंबी होती है। सम्मेलन की क्षमता सुनने-देखने से ज्यादा करने में होती है। उदाहरण के लिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है, ऐसा कहेंगे तो देशभक्तों को गुस्सा आ जाएगा। हो सकता है कि बदले में कोई हमें पाकिस्तान भी जाने के लिए कह दे। इसीलिए हमने इन्हीं सम्मेलनों के चलते बीच का रास्ता अपनाया है। देश को विकासशील जैसी सुंदर संज्ञा देकर बाहर से शेरवानी और अंदर से परेशानी वाली जैसी छवि का निर्माण किया है। ऐसा करने से कानों को सुकून

मिलता है और चेहरे पर बनावटी मुस्कान बनी रहती है। सम्मेलन कई तरह के होते हैं। उन्हीं में एक तरह का सम्मेलन है- 'मुद्दे को कैसे भटकाया जाए?' यह आजकल बड़े जोरों पर है। उदाहरण के लिए जब विपक्ष फलानी चीज की खरीद-फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तब जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार फलाने पर गोलीबारी करवा देती है। पेट्रोल-डीजल की कीमत के बारे में ज्यादा बहस न हो इसके लिए टमाटर-प्याज की कीमत बढ़ा देती है। सच्चे अर्थों में सम्मेलनों में 'अ' के बदले 'ब' और 'ब' के बदले 'अ' सुनाने की तरकीबें खोजी जाती हैं। विश्वास न हो तो हमारे उच्च सदनो को ही देख लें। आजादी के बाद से वही तो करते आए हैं। चूँकि गरीबी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। भ्रष्टाचार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भुखमरी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसीलिए सम्मेलन कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सच कहें तो यह देश हमसे नहीं सम्मेलनों से बना है। ■

वारिस

सौत का दुख
झेलती महिला
की कहानी



विक्रम सिंह

जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन के लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा पाते, न खुद को, न समाज को, न संस्कार, न दोस्त, न मातापिता को। सजा खुद काटनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही अघट घटा था प्रमिला के साथ, जिस के लिए कुसूरवार वह किसी को नहीं मानती। आज वह अपनेआप को कोसने लगी। ऐसा सुलूक तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। वह अपने उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उस ने प्रेमपाल सिंह से शादी के लिए हां कह दी थी। वह आत्मालाप कर रही थी, काश, प्रेमपाल से शादी की कुंडली मिली न होती। काश कि मैं मां की कोख में ही मर गई होती। अनेक बुरे खयाल उस के जेहन में बादलों की तरह उमड़घुमड़ रहे थे। उस दिन करवाचौथ था। उस दिन ही दूध वाले ने दूध देते वक्त मजाक-मजाक में कह दिया, भाभीजी, आज तो आप ने भी व्रत रखा होगा? प्रमिला ने मुसकराते हुए जवाब दिया था, हां। तब तो भाईसाहब की सौ साल उम्र हो जाएगी। भाईसाहब के लिए तो पचास-पचास साल की दुआएं मांगी जाएंगी। 50 आप और 50

**सौत को घर पर देखना
प्रमिला के लिए मौत से बढ़ कर था
लेकिन उस ने हालात से समझौता
कर लिया था, पर प्रकृति के भी खेल
निराले होते हैं।**

दूसरी मेमसाब द्वारा। वह दूध नाप-नाप कर बरतन में डालता रहा और व्यंग्य का बाण छोड़ कर चलता बना। प्रमिला का मन किया कि उसे डपट दे। मगर उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई थी। वह अपने दुख को दूसरों को सुनाने के बजाय खुद को कोसने लगती। नहीं भूल पाती वह उस दिन को जब प्रेमपाल ने अपना और प्रमिला का मैडिकल चैकअप करवाया था। उसे पता चल गया था कि वह मां नहीं बन सकती। वह उस के वंश को बढ़ा नहीं सकती, ब्याह के 7 साल बीत चुके थे। उस ने ही थकहार कर प्रेमपाल से जिद की थी कि किसी बड़े शहर में बड़े डाक्टर से जांच करवाई जाए। डाक्टर

ने जो बात बताई वह दिल को धड़काने से कहीं ज्यादा प्रमिला की जान लेने वाली थी। प्रमिला अपनेआप को धिक्कारती कि उस ने किसी बड़े डाक्टर के पास चैकअप करवाने की बात क्यों सोची? वैसे तो प्रेमपाल की कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि वह किसी बड़े डाक्टर के पास जाए। उसे अंदर ही अंदर डर लगता कि कहीं उस के सीमन में ही कोई कमी न हो पर प्रमिला की जिद के आगे झकना पड़ा था। हकीकत सामने अलग आ गई। प्रमिला में ही मातृत्व क्षमता नहीं थी। बावजूद इस के, प्रमिला ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उस ने अपने पति प्रेमपाल से बस इतना कहा था, डाक्टरों के कहने से क्या होता है। मुझे पूरा भरोसा है, आप पिता बनेंगे। उस दिन के बाद से प्रमिला ने सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और न जाने कितने तरह के व्रत-उपवास रखे। हरेक मंदिर में पूजा-अर्चना की पर बंजर जमीन बंजर ही रही। अब प्रमिला कहां जाती, किस से मन्त मांगती। अब उस की समझ के सबकुछ बाहर हो चुका था। उस के हृदय में अनेक प्रकार के संशय आने लगे थे।

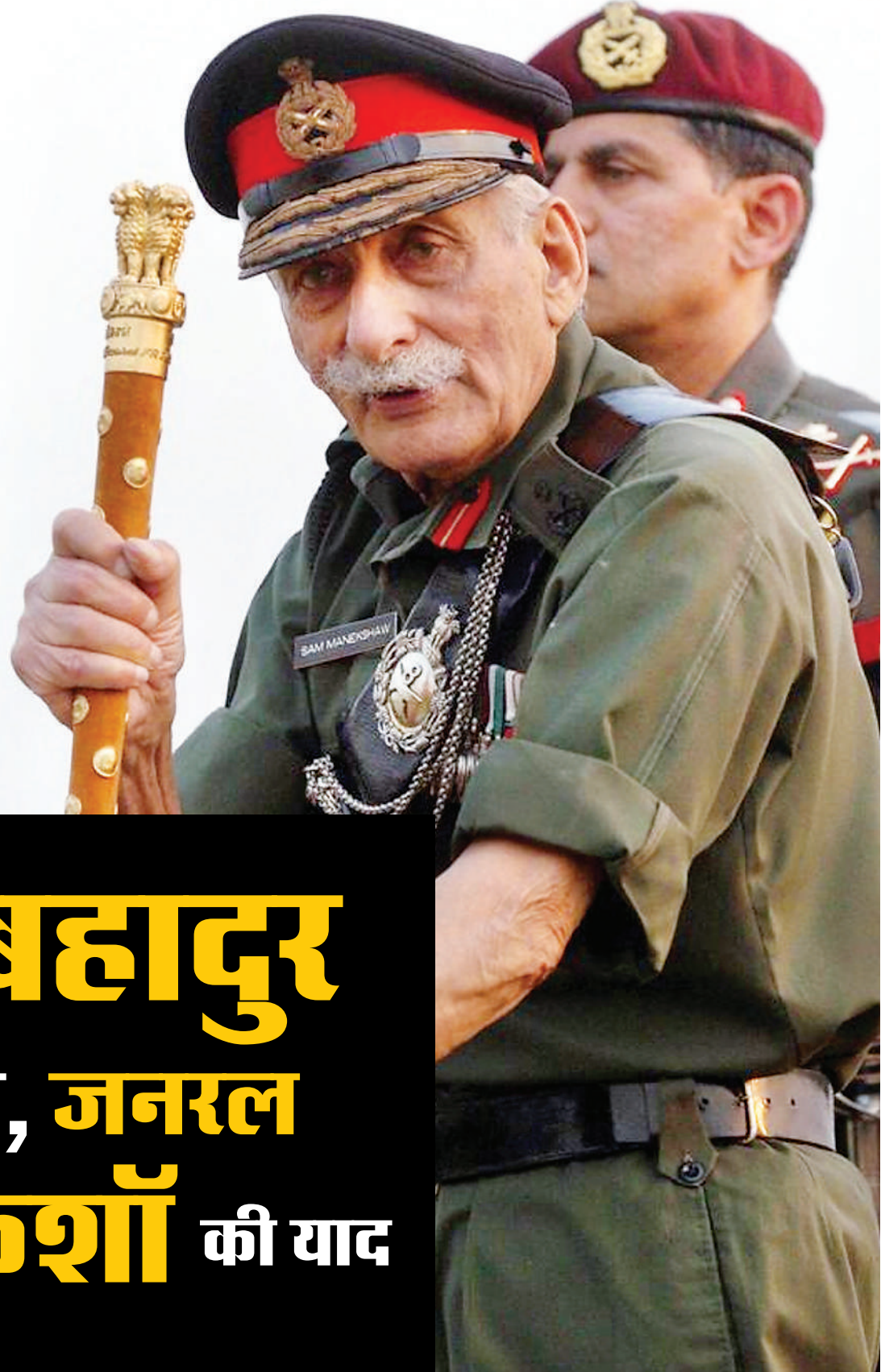
वह हालात से लड़ते-लड़ते हार रही थी। जैसे यशोदा मझ्या ने कृष्ण को पाला था, उसी तरह वह बच्चा गोद ले सकती थी। प्रमिला की बहन शर्मिला ने एक दिन अचानक ही कह दिया, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे गोद ले लो। जन्म तो मैं दूंगी मगर पालेगी तू। समझ कि इस बच्चे की मां तुम हो। दरअसल, प्रमिला की बड़ी बहन शर्मिला के 2 लड़के पहले से थे। दोनों अभी छोटे थे। दोनों बच्चों के बीच का फर्क भी मात्र 2 साल का ही था। दोनों बच्चे छोटे होने के कारण वह अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी। उस ने अपने पति राकेश से कहा था कि वह अपनी नसबंदी करवा ले, मगर उस ने टाल दिया था और जब 2 जवां दिल मिले तो चूक होनी ही थी और इस तरह शर्मिला के पेट में बच्चा आ गया। राकेश ने उसे अबॉर्शन करवाने से भी मना कर दिया था। शर्मिला पहले 2 बच्चों का पालन करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि तीसरे बच्चे के पालने की बात सोच कर वह सिहर उठी थी। प्रमिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहा जाए उस दिन प्रमिला इतनी खुश हुई कि उसे लगा ही नहीं कि उस की अपनी कोई संतान नहीं है। मौसम ने भी अपना रंग बदला। उस दिन खूब बारिश हुई। शाम का वक्त हो चला था। प्रमिला ने मौसम का मिजाज देख पति के कंपनी से आने के पहले पकौड़े तले और चाय बनाई। प्रेमपाल की शुरू से आदत थी, जब भी बारिश होती वे कहते, प्रमिला आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, पकौड़े हो जाएं तो मजा आ जाए। वह कितनी भी थकीमांदा हो पर प्रेमपाल की हर खुशी का खयाल रखती। खुशी का इजहार करने का इस से अच्छा तरीका और क्या हो सकता था, भला। मौसम भी सुहाना और पति के मनपसंद पकौड़े। मगर एकाएक जैसे मौसम बदला, सर्द हवा चुभने लगी। मेज पर रखे पकौड़े-चटनी फीके लगने लगे। प्रेमपाल ने बच्चे गोद लेने की बात अस्वीकार कर कहा था, मुझे पता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं लेकिन बच्चा पराया ही कहलाएगा। वंश चलाने के लिए पितृगुण विद्यमान रहना आवश्यक है। तुम चाहो तो हमारा वंश फल सकता है। प्रमिला विमूढ़ सी ताकती रही। कैसे? यह सवाल प्रमिला ने मन ही मन खुद से किया। शायद वह सच से पूरी तरह वाकिफ न थी या असलियत को वह सुनना नहीं चाहती थी। प्रेमपाल ने वह सच सामने ला कर रख दिया। प्रमिला को सच सुनते ही लगने लगा जैसे वह लहरों की मरजी से डोलने वाला कोई छोटा सा तिनका है, जिस की कोई दिशा निर्धारित नहीं। वह घृणा के साथ कमरे के अंदर चली गई। दरअसल, प्रेमपाल की ही कंपनी के एक साथी इकबाल ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया था। उस वक्त भी उस ने अपने मित्र इकबाल से कहा था, गोद तो मैं बच्चा ले सकता हूँ पर अपने दिल से उसे प्यार नहीं दे पाऊंगा। अपना खून तो अपना ही होता है। परम मित्र तो मित्र ही ठहरा। उस ने समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया या समस्या का समाधान उस के पास स्वयं चला आया।

एक दिन उस ने उस से एकाएक कहा- प्रेम, तुम से एक बात करनी थी। हां बताओ। तुम्हारे भले की बात है। पौढ़ी गांव की एक पहाड़न है। उस की 6 लड़कियां हैं। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढ रही है। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के पिता भी नहीं हैं। मैं ने तुम्हारे बारे में बताया है। तुम अगर चाहो तो तुम्हें अपना वारिस मिल सकता है। वह कैसे? उस की बड़ी विधवा लड़की की बच्चेदानी को किराए पर ले लेते हैं। बच्चों के पैदा होने तक आने वाला सारा खर्च तुम उठाओ। बच्चे की डिलीवरी से ले कर उस के परिवार की आवश्यकताओं तक को पूरा करोगे। किराया स्वरूप 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। उस की मां और लड़की राजी हैं? हां, मैं ने उसे समझ दिया है। जिस तरह रिकशेवाले, मजदूर आदि लोग अपना-अपना अंग श्रम देने के बदले पैसा लेते हैं, उसी तरह वंदना भी एक अंग कुछ दिनों के लिए किराए पर दे रही है। तुम एक दिन चल कर मिल लो। प्रेमपाल ने तुरंत उस गरीबन से मिलने और बात करने की ठानी। पौढ़ी गांव पहुंचते ही सब बदल गया। हुआ यों कि जैसे ही प्रेमपाल की नजर पहाड़न वंदना पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखता रह गया। नीली आंखें, गोरा बदन, भूरे बाल। उस की खूबसूरती देख कर वह फिसल गया। वह सबकुछ भूल गया। उस के ऊपर दीवानगी छा गई। इकबाल भी उस का भाव समझ गया। थोड़ी देर इधर-उधर की बातचीत के बाद वे दोनों अपनी कार में आ गए। इकबाल ने लौटते वक्त हंसते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। उस की हंसी और उस की बातें प्रेमपाल की गंभीरता से टकरा कर वापस लौट आईं। इकबाल ने तो प्रेमपाल के दिल की बात कह दी थी। प्रेमपाल सोचने लगा, हिंदू कानून दूसरी पत्नी रखने की इजाजत नहीं देता पर दूसरे ही पल उसे लगा कि कानून में छेद भी तो होते हैं। प्रमिला आसन संकट से सिहर उठी थी। किसी सुहागन के घर में सौत का आना, जीते जी नरक का दुख झेलना है। कमरे में बैठी वह तर्क देते कर खुद को देर तक समझती रही पर दिल और दिमाग के फासले को पाटना आसान नहीं होता। उस ने सबकुछ नियति पर छोड़ दिया था। मनुष्य जब सहीगलत का फैसला नहीं कर पाता, सबकुछ वक्त पर छोड़ कर निश्चित होने की कोशिश करने लगता है। प्रेमपाल अपनेआप को तसल्ली देता कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर की उम्मीद फिर उम्मीद का टूटना, एक सिलसिला सा बन गया था। यह नियति है या किसी का दर्द, छटपटाहट फिर एक वीरानी, जिस से प्रमिला को सच से डर लगने लगा था। डर जो अंदर तक हिलाता है, अनिश्चित दिनचर्या बनाता है, अनिश्चित रफ्तार दे कर मन को नीरसता की ओर मोड़ देता है। यहीं आ कर नारी होना भारी पड़ने लगता है। धीरेधीरे यह बात घर की चारदीवारी से फुदक कर जहांतहां पहुंच गई थी। गांव, शहर, जिला, जहां-जहां प्रमिला के जानने वाले थे, सब ने अपनी-अपनी तरफ से सुझाव दिए। इन सुझावों से प्रमिला की

चिंता दोहरी-तिहरी होती गई। प्रमिला ने जो उम्मीद की आंखें प्रकृति के ऊपर टिका रखी थीं वहां से भी उस ने आंखें हटा ली थीं क्योंकि प्रेमपाल अपनी चाहत की भट्टी में कड़ियों की आहुति देने को आतुर था। प्रेमपाल ने शादी की तारीख रख इतनाभर कहा था, प्रमिला, तुम इसे अगर गलत समझती हो तो गलत लगेगा। इसे व्यावहारिक दृष्टि से सोचो तो फिर वह सही लगने लगेगा। उस दिन के बाद से प्रमिला ने सोच लिया था कि वह यह घर छोड़ अपने पिता के पास चली जाएगी। उस का बूढ़ा पिता, जो शुगर, ब्लडप्रेसर आदि बीमारियों से पीड़ित एक मामूली सा किसान था। 3 बेटियों के ब्याह के बाद कर्ज में लदा पड़ा था। आखिर प्रमिला किस तरह उन पर बोझ बने पर सुनने में यह भी आया था, प्रेमपाल ने अपने ससुर निरंजन से यह बात साफ-साफ कह डाली थी, या तो प्रमिला अपनी सौतन को स्वीकार कर ले या फिर मुझे छोड़ दे। निरंजन ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल, निरंजन सोच नहीं पा रहे थे कि किन शब्दों से अपनी बेटी प्रमिला को आश्वस्त करे। प्रमिला इस वजह से चुप हो गई थी। दरअसल, उस ने मौन से समझता कर लिया था। एक दिन प्रेमपाल बारात लेकर अपनी दूसरी शादी के लिए निकल पड़ा। प्रेमपाल की बारात तो गई मगर सिर्फ 4 लोग ही बारात में गए। न कोई बंडबाजा, न सजावट, न ही सिर पर सेहरा। यों उसने अपने कई मित्रों, रिश्तेदारों को कहा तो था पर सब ने इस शादी में शामिल होना शर्मिंदगी व अपना अपमान समझा। गोया प्रेमपाल ब्याह करने नहीं, बच्चे पैदा करने की मशीन लाने जा रहा हो। सच भी यही था। ब्याह के 3 साल में तीन बच्चे हुए। जब वंदना ने पहला बच्चा जना तो प्रेमपाल ने आसमान की तरफ सिर उठाया। फिर उस ने फूटफूट कर खुशी के आंसू बहाते हुए बच्ची को प्रमिला की गोद में दिया जो अवसाद का वह टुकड़ा, जिसे वह कई महीनों से चुभला रही थी, अब नदारद था। उसे मातृत्व का एहसास हुआ और उस ने उसी वक्त वंदना से कह दिया, यह बच्ची तुम मुझे गोद दे दो। वंदना ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया, आप ही इस की बड़ी मां हैं, पालना तो आप को ही है। दो लड़कियों के बाद तीसरा लड़का तो हुआ मगर 3 महीने बाद ही उस ने भी दम तोड़ दिया। पैदा होने के बाद से ही उसे दवाइयों के सहारे पाला जा रहा था। दवाइयों के सहारे वह 3 महीने खींचतान कर जिया तो जरूर पर अगले महीने ही उस ने दम तोड़ दिया। बड़े-बड़े डाक्टरों की दवा खाते-खाते ठीक होने के बजाय उस का स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया। सुनने में यह भी आया था कि जब वंदना का तीसरे बच्चे के वक्त 8वां महीना चल रहा था, उसकी किसी बात को ले कर प्रेमपाल से कहासुनी हो गई थी। प्रेमपाल ने आव देखा न ताव, उस की धुनाई कर दी। उसी वक्त बच्चे को पेट में चोट लग गई थी। दूसरे दिन वंदना को पेट में जोर से दर्द उठा। आनन-फानन वंदना को अस्पताल में भरती कराया। ■



सैम हॉरमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशाँ को देश 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारतीय थल सेना का कुशल नेतृत्व करने वाले एक सेनाध्यक्ष के रूप में कृतज्ञ भाव से याद करता है। वे फील्ड मार्शल का पद हासिल करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। अब उनके जीवन पर आधारित फिल्म सैम बहादुर के रीलज होने के साथ ही यह मौका है कि हमारे सारे देशवासी खासकर के युवा पीढ़ी उनकी शख्सियत को फिर से जाने-समझे।



सैम बहादुर के बहाने, जनरल मानेकशाँ की याद

आर.के. सिन्हा

उन्हें सैम मानेकशॉ और सैम बहादुर भी कहा जाता था। वे 1969 में भारत के सेनाध्यक्ष बने थे। इससे पहले उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के साथ-साथ भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ हुई तमाम जंगों में अहम भूमिका निभाई थी। सैम मानेकशॉ समर नीति के गहरे जानकार थे। पर उनकी जुबान भी फिसलती रहती थी, जिसका उन्हें कई बार बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा था। वे 1971 की पाकिस्तान के साथ हुई जंग में विजय का क्रेडिट जाने-अनजाने खुद लेने की फिराक में लगे रहते थे। उन्होंने एक बार तो एक इंटरव्यू में यहां तक दावा कर दिया था कि अगर वे पाकिस्तान सेना के प्रमुख होते तो 1971 की जंग में पाकिस्तान विजयी हो गया होता। उनके इस दावे पर तब भी बहुत बवाल कटा था।

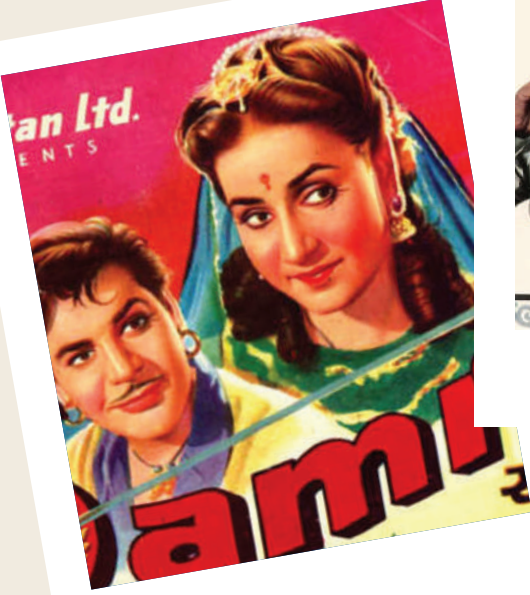
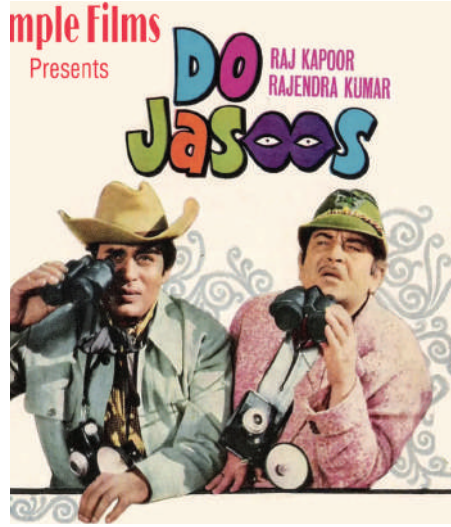
दरअसल जंग सेना के साथ-साथ सारा देश ही लड़ता है। इसलिए विजय भी सम्पूर्ण देश की ही होती है। हां, रणभूमि के वीरों का अपना विशेष महत्व तो होती ही है। 1971 की जंग के नायकों की बात होगी तो अनेकों नायक सामने आएंगे। इस बाबत जनरल जगजीत सिंह अरोरा और जनरल जैकब से लेकर सेकिंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी याद भी किया जाएगा। उस जंग में भारत की विजय पर बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक अरुण खेत्रपाल के पराक्रम की चर्चा ना हो जाए। उनके पिता भी उस जंग में लड़ रहे थे। अरुण खेत्रपाल ने पंजाब-जम्मू सेक्टर के शकरगढ़ में शत्रु के दस टैंक नष्ट किए थे। वे तब मात्र 21 साल के थे। इतनी कम आयु में अब तक किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला है। नोएडा का अरुण विहार सेकिंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नाम पर ही है। उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकाडमी से जून, 1971 में ही ट्रेनिंग खत्म की। उसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई। अरुण खेत्रपाल की स्क्वेड्रन 17 पुणे हांस 16 दिसम्बर 1971 को शकरगढ़ में थी। वे टैंक पर सवार थे। टैंकों से दोनों पक्ष गोलाबारी कर रहे थे। वे शत्रु के टैंकों को बर्बाद करते जा रहे थे। इसी क्रम में उनके टैंक में भी आग लग गई। वे शहीद हो गए। लेकिन उनकी टुकड़ी उनके पराक्रम को देखकर इतनी प्रेरित हुई कि वह दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी। युद्ध में भारत को सफलता मिली। अरुण को शकरगढ़ का टाइगर कहा जाता है। 1971 की जंग से जुड़ी एक यादगार फोटो को देखकर भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। उस फोटो को देखकर हरेक हिन्दुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के साथ पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खाँ नियाजी बैठे हैं। नियाजी अपनी सेना के आत्मसमर्पण करने संबंधी एक पेपर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उस चित्र में भारतीय सेना के कुछ आला अफसर प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। उनमें जनरल

खैर, सैम मानेकशॉ के जीवन पर बनी फिल्म से देश की युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिलेगी। सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर भी प्रमोट कर दिया था। हालांकि, वे 1975 के आस-पास दिल्ली से चले गए थे। उसके बाद उनका दिल्ली आना-जाना कम ही होता था। मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में मृत्यु हुई थी। फिर वहां ही उनकी सादगी से अंत्येष्टि कर दी गई थी। सैम मानेकशॉ की मृत्यु के ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि सरकार को सैम मानेकशॉ का अंतिम संस्कार दिल्ली में पूरे सैनिक सम्मान से करना चाहिए था।

जे.एफ.आर जैकब भी हैं। युद्ध संवाददाता के रूप में मैंने जनरल जैकब के साथ काम किया है और देखा है कि वे किस जांबाज किस्म के सेना नायक थे। 1971 के युद्ध में जैकब की रणनीति के तहत भारतीय सेना को अभूतपूर्व कामयाबी मिली थी। भारत में जन्मे वे यहूदी थे और समर नीति बनाने में महारत रखते थे। पाकिस्तान सेना के रणभूमि में परास्त करने के बाद जनरल जैकब ने नियाजी से अपनी फौज को आत्मसमर्पण का आदेश देने को कहा था। जैकब के युद्ध कौशल का ही परिणाम था कि नब्बे हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियारों समेत भारत की सेना के समक्ष घुटने टेके। आज के दिन जनरल जैकब राजधानी के हुमायूँ रोड के यहूदी कब्रिस्तान में चिर निद्रा में हैं।

अगर बात जनरल अरोड़ा की करें तो उन्होंने 1971 की जंग में भारतीय सेना को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान में घुसने के आदेश दिये थे। उनकी इस रणनीति की वजह से ही हमारी सेना देखते ही देखते ढाका पहुंच गई थी। जनरल अरोड़ा ने जीवन भर 1984 में सिख विरोधी दंगों के दोषियों को दंड दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष किया था। उधर, फ्लाईंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भी 1971 की जंग के एक महान नायक थे। आपने उनके शौर्य की कथाएं अवश्य सुनी होंगी। जब जंग चालू हुई वे तब राजधानी के रेस कोर्स क्षेत्र में रहते थे। उस जंग के लिए 14 दिसम्बर 1971 का दिन खास था। उस दिन फ्लाईंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने पाकिस्तान के दो लड़ाकू सेबर जेट विमानों को ध्वस्त कर दिया था। उन्हें उस जंग में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। यदि भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना के गले में अंगूठा डाल दिया था, तो इसका कहीं न कहीं श्रेय एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ को भी जाता है। वे 1971 के युद्ध के दौरान सहायक वायुसेनाध्यक्ष के पद पर थे। वे जंग के समय शत्रु से लोहा लेने की रणनीति बनाने के अहम कार्य को अंजाम दे रहे थे। लतीफ लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने, युद्ध की प्रगति तथा यूनितों की आवश्यकताओं पर भी नजर रख रहे थे। लतीफ

शिलांग स्थित पूर्वी सेक्टर में थे, जब पाकिस्तान ने हथियार डाले थे। दिल्ली कैंट में उस महान योद्धा के नाम पर एक सड़क भी है। इदरीस हसन ने 1948 और 1965 की जंगों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। लतीफ के एयर फोर्स चीफ के पद पर रहते हुए इसका बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण हुआ। उन्होंने जगुआर लड़ाकू विमान की खरीद करने के लिए सरकार को मनाया था। तो यह कोई दावा नहीं कर सकता कि उसकी वजह से भारत किसी जंग में जीता। बहरहाल, सैम मानेकशॉ को प्यार से सैम बहादुर इसलिए कहा जाता था। क्योंकि, उनका संबंध गोरखा रेजीमेंट से था। वे जब सेनाध्यक्ष थे तब आर्मी हाउस की निगाहबानी गोरखा रेजीमेंट के जवान ही किया करते थे। बता दें कि राजधानी में 4, राजाजी मार्ग के बंगले को आर्मी हाउस कहा जाता है। इसी में सेनाध्यक्ष रहते हैं। इसी में जनरल के.एम.करिया, जनरल के. सुंदरजी, एन.सी. विज जैसे महान सेनाध्यक्ष रहे हैं। देश की आजादी के बाद से ही सेनाध्यक्ष इधर ही रहते रहे हैं। सैम मानेकशॉ भी भारतीय सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए 4, राजाजी मार्ग के आर्मी हाउस में ही रहा करते थे। कहते हैं कि वे सुबह अपने बंगले के बाहर भी सैर करने के लिए निकल जाया करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी हुआ करती थीं। वहां पर अगर कोई शर्रस सड़क पर चलते हुए उन्हें नमस्कार करता तो वे उसका आदरपूर्वक उत्तर भी देते थे। उनमें जनरल पद की ठसक नहीं थी। खैर, सैम मानेकशॉ के जीवन पर बनी फिल्म से देश की युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिलेगी। सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर भी प्रमोट कर दिया था। हालांकि, वे 1975 के आस-पास दिल्ली से चले गए थे। उसके बाद उनका दिल्ली आना-जाना कम ही होता था। मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में मृत्यु हुई थी। फिर वहां ही उनकी सादगी से अंत्येष्टि कर दी गई थी। सैम मानेकशॉ की मृत्यु के ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि सरकार को सैम मानेकशॉ का अंतिम संस्कार दिल्ली में पूरे सैनिक सम्मान से करना चाहिए था। ■



हिंदी फिल्मों की कहानियों और गीत-संगीत से भी गूंजती रही हैं आवाजें

"हैप्पी न्यू ईयर"



हैप्पी न्यू ईयर शब्द गूंजते ही फिजा में एक अजीब तरह की खुशगवारी और रोमांच बिखरने लगता है। नए साल के जश्न को हिंदी सिनेमा ने भी भरपूर तवज्जो दी है, कभी फिल्मों की कहानी का हिस्सा बनाकर तो कभी फिल्मों के गीत-संगीत में पिरोकर सिनेदर्शकों को जश्न में डुबोया है। कई फिल्मों के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं या फिर यूं कहें कि वे नए साल की पार्टियों के जश्न को चौगुना कर जाते हैं।

डॉ. महेश चंद्र धाकड़

फिल्मों में नए साल से जोड़कर गीत और संगीत भी खूब पेश किया गया है, जो लोकप्रिय भी हुआ है। पुरानी फिल्मों से लेकर आज तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है और इन गीतों को न्यू ईयर की पार्टियों में बजते हुए सुना भी जाता रहा है। इन्हीं गीतों पर थिरकते हुए युवा नए साल का जश्न मनाते हैं। नए साल के मौके पर न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम्स में टीवी और रेडियो पर भी इन्हीं गीतों की धूम रहती है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ग्लैमरस पार्टियों में इनको डिस्क जॉकी और वीडियो जॉकी भी खूब बजाते हैं। साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म 'सम्राट' का एक गीत याद आता है। राजेंद्र कृष्ण लिखित इस गीत को हेमंत कुमार ने अपने संगीत से सजाया है। आशा भोंसले ने इसको कोरस में साथियों के साथ गाया है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह गीत रेडियो सीलोन पर काफी साल तक नए साल की दस्तक पर मानो एक परंपरा की तरह से सुनाई देता रहा।

सबको मुबारक नया साल...!
नया साल ये नया साल
ये नया साल ये नया साल
सबको मुबारक नया साल
साल पुराना हुआ फसाना...!

1975 में रिलीज फिल्म 'दो जासूस' का भी एक लोकप्रिय गीत है। राजकपूर और राजेंद्र कुमार ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। रवींद्र जैन के संगीत से सजे गीत को मुकेश और मौ. रफ़ी ने राज कपूर और राजेंद्र कुमार के लिए गाया। इस फिल्म के गीत हसरत जयपुरी और रवींद्र जैन ने लिखे थे।

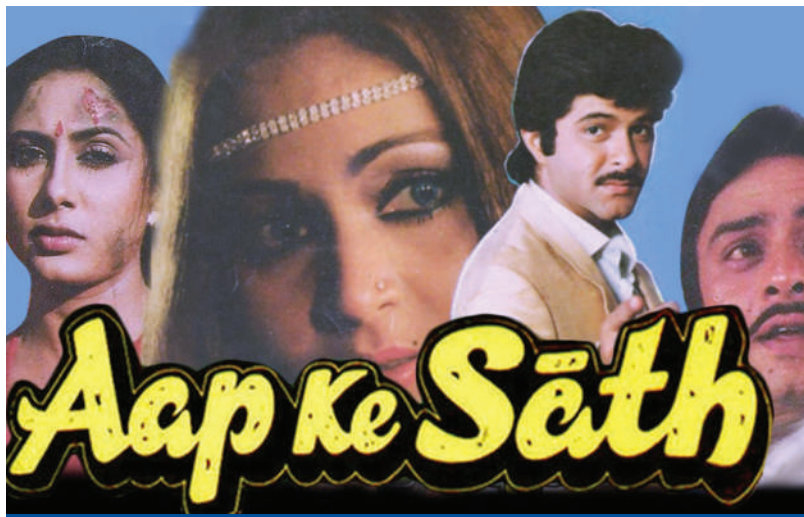
साल मुबारक साहेब जी
लो लो आज पियो हँस के
दो घूंट सोमरस के
के साल भर इसका नशा रहेगा
जो आज पियो पीता सदा रहेगा
साल मुबारक साहेब जी...!

इसी 'दो जासूस' फिल्म का एक और गीत है। जिसको कि शैलेंद्र सिंह और साथियों ने गाया है। फिल्म का यह गीत भी लोकप्रिय हुआ था।

कल के तराने हुए पुराने
गाओ रे मेरे संग कोई गीत नया
हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू...!

वर्ष 1980 में रिलीज फिल्म 'नजराना प्यार का' में निदा फाजली का लिखा एक गीत आशा भोंसले ने बेटे हेमंत भोंसले के संगीत निर्देशन में अमित कुमार और अनवर के साथ गाया था, जो काफी लोकप्रिय भी हुआ था।

नया साल आये, तमाशे दिखाये
किसी को हँसाए, किसी को रुलाये
नया साल आये...
जहाँ है उजाला वहीं है अंधेरा
मुकद्दर पे काबू, न मेरा न तेरा
ये जीवन पहेली, समझ में न आये



नया साल आये, तमाशे दिखाये...!

वर्ष 1986 में रिलीज हुई फिल्म 'आप के साथ' का एक गीत भी बखूबी याद आता है। अनिल कपूर पर फिल्माए इस गीत को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की पार्टियों में खूब बजते हुए सुना जा सकता है। आनंद बख्शी लिखित गीत को शब्बीर कुमार ने अपनी आवाज में यादगार बना दिया है-

आने वाले साल को सलाम
जाने वाले साल को सलाम
नये साल का पहला जाम, आपके नाम
हैप्पी न्यू ईयर...!
हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर...!

इसके अलावा फिल्मों के कथानकों में भी नए साल का जिक्र खास अंदाज में छिड़ा है। कई फिल्मों में इससे कुछ और आगे बढ़कर नया साल उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। इस नाम के आकर्षण को भुनाने और फिल्म की कहानी में इसकी अहमियत को दर्शाने के लिए कई निर्माताओं ने तो अपनी फिल्मों के नाम के साथ में न्यू ईयर शब्द को भी प्रमुखता से जोड़ा है।

■ वर्ष 2010 में निर्देशक शकुन बत्रा की फिल्म 'अनजाना अनजानी' में रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे, इस फिल्म में इन दोनों की मुलाकात ऐसे मोड़ पर होती है जब दोनों ही अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, और न्यू ईयर की शाम को दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं।

■ निर्देशक शकुन बत्रा के निर्देशन में वर्ष 2012 में आई फिल्म 'एक मैं और एक तू' में करीना

कपूर और इमरान खान मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के एक सीन में क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक दिखाया है।

■ 2013 में आई अयान मुखर्जी निर्देशित फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में न्यू ईयर की शाम को रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण को प्रपोज करते हैं। इस खास सीन में रणवीर, दीपिका के घर गुब्बारे और केक लेकर पहुंचते हैं और उन्हें किस तक कर लेते हैं। फिर दीपिका को अंगूठी पहनाकर, रणवीर उनको प्रपोज कर देते हैं।

■ 2014 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फराह खान द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवान शाह और जैकी श्रॉफ सरीखे कलाकार थे। यशराज फिल्म्स ने इसे वितरित किया था। इस फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल लेता है जो शहर और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लेते हैं।

■ टी-सीरीज के बैनर तले भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित फिल्म 'आई लव एनवाई', जिसे 'आई लव न्यू ईयर' नाम से भी जाना जाता है। साल 2015 में रिलीज हुई यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। राधिका राव और विनय सपू निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल और कंगना रनौत ने प्रभावी अभिनय किया। फिल्म के कथानक में एक खूबसूरत संगीतकार और एक गंभीर वॉल स्ट्रीट बैंकर नए साल की पूर्व संध्या में एक-दूजे से मिलते हैं, आगे चलकर उनके बीच प्यार पनप जाता है। ■

काली स्याह रात को...

काली स्याह रात को
नई सुबह के इंतजार में
गुजरते देखा है
एक मामूली से शख्स को
लोगों की उम्मीदें बनते देखा है
साथ ही देखा है
हर दिन को ढलते हुए
रात के करीब जाने के लिए
और देखा है
लोगों की उम्मीदों को टूटते हुए
अब तो समझ भी आता है
क्यों टूटती है उम्मीदें
क्योंकि हमको नहीं होता
खुद पर भरोसा
इसलिए टूटती है उम्मीदें
ढलता है दिन
और आ जाती है काली स्याह रात .

-हरीश भट्ट



With Best Compliments from

Jai Kumar Agarwal

Managing Director
+91-9918700801



GYAN DAIRY

jai@agarwal@gyandairy.com

Dream of Healthy India



NOVA[®]

DAIRY PRODUCTS



घी, दूध, दही, छाछ,
पनीर और डेयरी व्हाईटनर

STERLING AGRO INDUSTRIES LTD.

E-mail: sterling@steragro.com, sterling@steragro.biz ★ Website: www.steragro.com

Works : Village - Bhitaua, Soron Road, Kasganj-207123 (UP)

For Distributorship, Please Contact Mr. Adarsh Sharma, Mob.: 9319554050

Mohr